पंचवर्षीय विज़न

2019-2024

भारत सरकार

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली

विषय-सूची

क.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के परिवर्तन की पृष्ठभूमि	2
ख.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कार्य पद्धतियाँ	4
ग.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली-विज़न 2024	6
घ.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली-परिवर्तनशील विषय-वस्तु	7
ड.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली-परिवर्तनकारी कार्यनीतियाँ	11
च.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली-कार्यान्वयन विज़न	13
	• कार्यनीति I - संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण	13
	• I. क. शासकीय सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति	14
	• I. ख. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का सुदृढ़ीकरण	14
	• I. ग. सर्वश्रेष्ठ वैश्विक कार्यपद्धतियों को अंगीकार करना	15
	• कार्यनीति II - प्रौद्योगिकीय और भौतिक संरचना का सुदृढ़ीकरण	16
	• II. क. सांख्यिकीय उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना	17
	• II. ख. सांख्यिकीय सर्वेक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना	18
	• II. ग. प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का वास्तुशिल्पीय सुदृढ़ीकरण	18
	• II. घ.पंजीयनों का समन्वित समेकन	19
	• II. ड.भौतिक संरचना	21
	• कार्यनीति III - प्रभावी मानव पूंजी प्रबंधन	21

छ.	संशोधित राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली - अपेक्षित परिणाम	25
ज.	पंचवर्षीय कार्यनीतिक लक्ष्य और गतिविधियाँ	26
	I -विषय-वस्तु, लक्ष्य और कार्यनीतिक गतिविधियाँ	26
	II – विज़न-2024 के लिए आक्रमणशील समयसीमा	28
	III - विभिन्न कार्यनीतिक गतिविधियों का विवरण और समयसीमा	29

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

पंचवर्षीय (2019- 2024) विज़न प्रलेख

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय -विज़न 2024

"जनता के लिए योजना और प्रबल प्रसारकार्य हेतु वास्तविक- समय निविष्टियाँ प्रदान करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़करना।"

एकीकृत सांख्यिकीय दृष्टिकोण

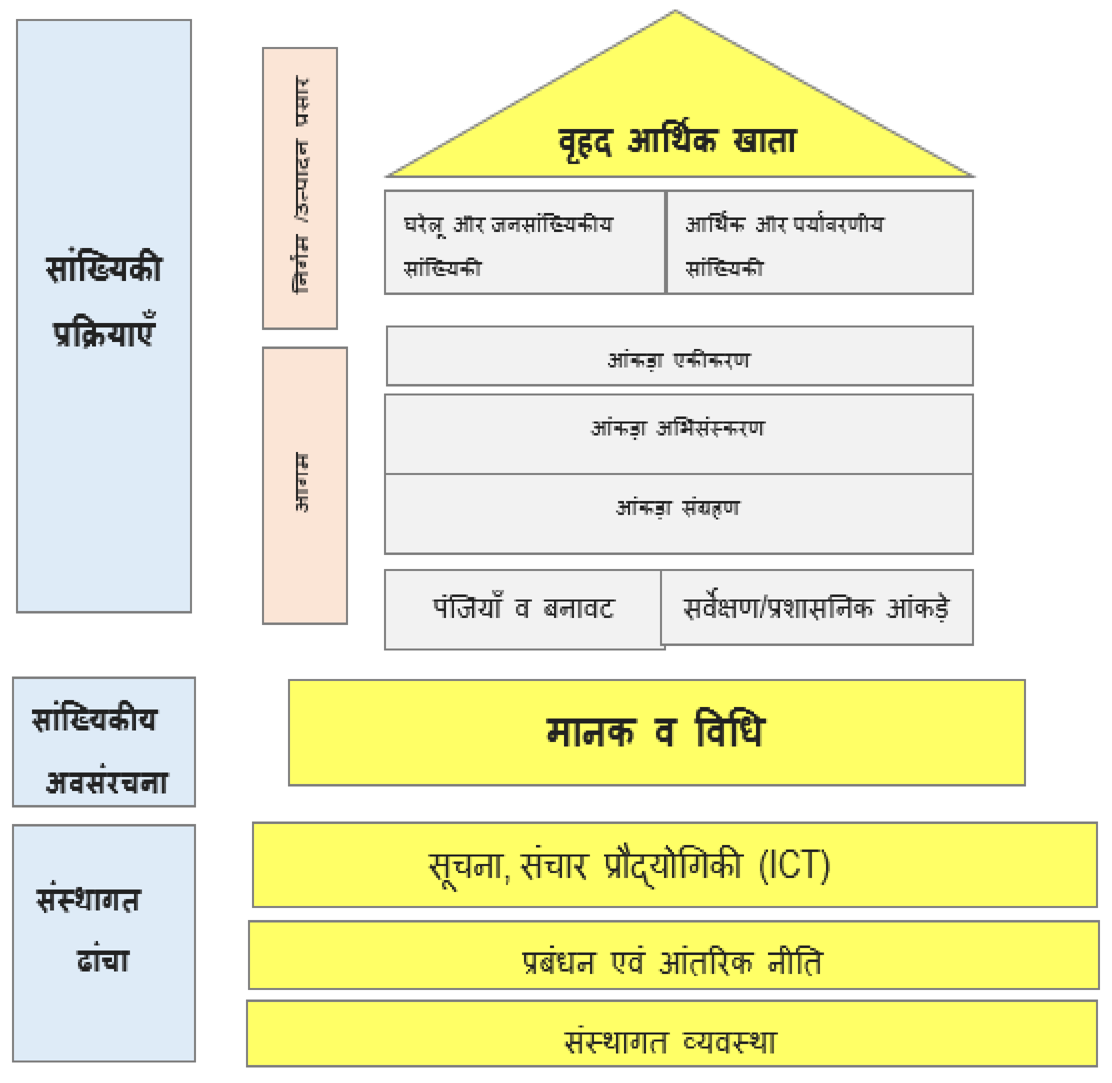

अध्याय -1

क. राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के परिवर्तन की पृष्ठभूमि

1.1 शासकीय सांख्यिकी प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्यआगे के सुधार के लिए नीति निर्माण, निगरानी, मूल्यांकन और सिफारिशों के आधार पर साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की सुविधा के लिए समय पर, विश्वसनीय और व्यापक आँकड़े प्रदान करना है। भारतीय संदर्भ में, शासकीय सांख्यिकी प्रणाली

केंद्रस्तर पर भारत सरकार (भा.स.) के विभिन्न मंत्रालयों के बीच पार्श्ववत् विकेंद्रीकृत, तथा केंद्र और राज्यों के बीचलंबवत् विकेंद्रीकृत है ।

1.2 **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय(एन एस ओ),** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के एकीकृत विकास की योजना और सुगमता हेतु बुनियादी अभिकरण है। यह सामाजिक-आर्थिक-जनसांख्यिकीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर उभरती और विकसित जानकारी /आँकड़ों की जरूरतों के अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एन एस ओ शासकीय सांख्यिकी, उभरती अवधारणाओं, परिभाषाओं, आँकड़ा संग्रहण की कार्यप्रणाली और वर्गीकरण, आँकड़ों के प्रसंस्करण और परिणाम जारी करने के क्षेत्र में मानदंड और मानकों को बनाता और विकसित करता है। यह सांख्यिकीय प्रक्रियाओं और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने,आँकड़ों की उपलब्धता में अंतराल की पहचान करने व सांख्यिकीय कार्यों के दोहराव और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने, तथा विभिन्न सांख्यिकीय उत्पादों कोप्रकाशित करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों की सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय भी करता है। एनएसओ सांख्यिकीय मानकों को पूरा करने, मॉडल सर्वेक्षण करने, जनगणना और प्रशासनिक आंकड़ों में सुधार करने की गतिविधियों व मामलों पर केंद्रीय मंत्रालय / विभागों और राज्य सरकारों को सलाह भीउपलब्ध करवाता है। इसके अतिरिक्त, एमओएसपीआई का कार्यक्रम कार्यान्वयन (पीआई) स्कंध, समय और लागत बढ़ जाने वाली 150 करोड़ रुपये से अधिक रुपये की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) को भी लागू करता है।

1.3 दुनिया भर के देश तेजी से प्रमुख प्रौद्योगिकीय और सामाजिक-आर्थिक बदलावों का सामना करते हुए अपनी राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों के महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण पर जोर दे रहे हैं। इन परिवर्तनों के अनुरूप, शासकीय सांख्यिकीय परिदृश्य अधिक जटिल होता जा रहा है, नीति निर्माताओं की अपेक्षाएं तेजी से बढ़ रही हैं, तथा व्यवस्था को और अधिक कुशल और अभिनव तरीकों से सर्वोत्तम संभव आंकड़े देने के लिए चुनौती मिल रही है। यह भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के लिए सही भी है। चूंकि सरकारी आंकड़ों में सरकारी सांख्यिकी को प्रस्तुतकिया जाता है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक वस्तु माना जाता है, और इस प्रकार यह आवश्यक है कि वे सांख्यिकी के संग्रह और प्रसार के विधियों के बारे मेंकुछ बुनियादी सिद्धांतों, जैसे व्यावसायिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता का

अनुपालन करें। ये सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जनवरी, 2014 में अपनाए गए, शासकीय सांख्यिकी के संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों में निहित हैं। भारत ने इन सिद्धांतों को मई, 2016 में एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव के माध्यम से अंगीकार किया है।

1.4 भारत सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के एक नए शीर्ष पर है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बढ़ते प्रवेश से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता आई है और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। फलस्वरूप, उपलब्ध जानकारी की मात्रा जनता तक बेहतर पहुंच के साथ तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्तरीय डिजिटल सेवाओं की शुरुआत के साथ डिज़िटल-भारत के अंतर्गत की गयी पहल ने ई-गवर्नमेंट परिदृश्य को बदल दिया है। इन नई सेवाओं से आँकड़ों का प्रवाह सरकार को निर्णय समर्थन के लिए नए और समय पर आँकड़ों के स्रोतों का लाभ उठानेमें सक्षम बनाता है। केंद्र और राज्य सरकारें आँकड़ों के इन नए स्रोतों कालाभ उठाने के अपने प्रयासों को तेजी से बढ़ा रही हैं। नीति निर्माताओं को न केवल विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में जानना है, बल्कि मध्य-मार्ग सुधारों को प्रभावित करने के लिए उनके प्रभाव और परिणामों की बेहतर कल्पना करना भी है, जो अब प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ संभव हो रहे हैं। इसने प्रसार, और आँकड़ों केउपयोग को उत्प्रेरित किया है जो एक अभूतपूर्व गति से हो रहे हैं। ये घटनाक्रम राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के लिए विभिन्न स्रोतों में सूचना प्रवाह को संरेखित और परिवर्तित करने के लिए एक नया अवसर प्रदान करते हैं ताकि एक एकीकृत चित्र अधिक प्रभावी और समय पर नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए उभरे।

1.5 डिजिटल डाटा क्रांति द्वारा संचालित **औद्योगिक क्रांति 4.0** की इस पृष्ठभूमि में, समाज और नीति निर्माताओं की समकालीन मांगों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। सांख्यिकीय उत्पादों को अधिक विश्वसनीय, समझने में आसान और सुलभ होने की आवश्यकता है। यू एस डी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए सरकार की पहल को अर्थव्यवस्था के बहु-आयामी मापदंडों की वास्तविक समय निगरानी की आवश्यकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण के विकास को मापने के लिए उद्देश्यपूर्ण और बेहतर मापन प्रदान करने में एक सतत और अग्रसक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

1.6 भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली इस परिवर्तन यात्रा में अकेली नहीं है और यह कई अन्य विकासशील और विकसित देशों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपनी सांख्यिकीय प्रणालियों के

आधुनिकीकरण में शामिल करती है और साथ ही सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए आँकड़ों की मांगों को पूरा करने के लिए विकसित होती है। एसडीजी प्रतिबद्धता के तहत पूर्ति, स्थान, लिंग, आयु, आय समूह और विकास के अन्य आयामों से विसमूहित गुणवत्ता आँकड़ों और सांख्यिकी की आवश्यकता हेतु अपेक्षित नई मांगें भी रखती है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इन प्राथमिकताओं को सम्बोधित करने के लिए समय पर और मजबूत शासकीय आंकड़ों के साथ इन मांगों को अनुकूल करने का बीड़ा उठा रहा है।

1.7 विकेंद्रीकृत सांख्यिकीय ढांचे में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए भारत में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और सुशासन के लिए देश की उच्च प्राथमिकता वाली जानकारी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी गतिविधियों को संरेखित करना चाहता है।

ख. राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धतियाँ

2.1 संयुक्त राष्ट्र और इसके विशिष्ट अभिकरण विभिन्न दिशानिर्देश और मानक लाते हैं जिन्हें सदस्य देशों में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसारअपना सकते हैं। इसके अलावा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयअपनी सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के लिए आईएसओ: 9000 प्रमाणन का अलग-से लक्ष्य रख रहा है, और वर्तमान में, एनएसओ के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, मूल्य सांख्यिकी प्रभाग तथा सर्वेक्षण गठन और अनुसंधान प्रभाग आईएसओ: 9000 प्रमाणित हैं । मंत्रालय ने अप्रैल, 2018 में भारत में सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रशासित होने के लिए उनकी गुणवत्ता प्रक्रियाओं पर स्व-मूल्यांकन अंकों का हिसाब प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे को अधिसूचित किया है। यह **संयुक्त राष्ट्र के गुणवत्ता आश्वासन ढांचे** पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार किया गया सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के सांख्यिकीय प्रणालियों के समेकन के लिए एक जीवंत मंच प्रदान करता है और इसका उपयुक्तता से लाभ उठाया जाएगा।

2. 2 यूएन **"एकीकृत आर्थिक सांख्यिकी पर दिशानिर्देश"** भी लाया है जो देश की आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए एक सुसंगत ढांचे की आवश्यकता के अनुकूलन में एकीकृत आर्थिक आंकड़ों के एक समूह

को तैयार करने में देशों का, विशेष रूप से एक निरंतर वैश्विक अर्थव्यवस्था में, मार्गदर्शन करता है। एकीकृत आर्थिक आँकड़े, नीति और विश्लेषणात्मक उपयोगों के लिए देश की आर्थिक गतिविधि का एक सुसंगत और विश्वसनीय मूल्यांकन प्रदान करते हैं। यह तब और अधिक महत्व रखता है जब देशों को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की प्रगति की निगरानी करने की आवश्यकता होती है।

2.3 **एकीकृत आर्थिक आँकड़े** आर्थिक आँकड़ों का एक समूह है जो नीति, व्यवसाय और अन्य विश्लेषणात्मक उपयोगों के लिए आर्थिक गतिविधियों की एक सुसंगत और स्पष्ट तस्वीर को दर्शाते हैं। आर्थिक आँकड़ों का समेकन सांख्यिकीय मिलान के लिए सामान्य अवधारणाओं, परिभाषाओं, अनुमान विधियों और आँकड़ा स्रोतों के उपयोग के संबंध में है। आज के वैश्विक संदर्भ में, सांख्यिकीय सेवाओं के उपयोगकर्ता अधिक और बेहतर आंकड़े मांगते हैं, और एकीकृत आर्थिक आँकड़ों के लिए उपयोगकर्ता की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में सांख्यिकीय सेवा प्रदाताओं को सक्रिय होने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा; स्थिरता, सामाजिक प्रगति और कल्याण की माप पर हाल ही में उभरते हुए कई उपक्रमों ने उन जटिल मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए एकीकृत और सुसंगत शासकीय आंकड़ों की आवश्यकता को बढ़ाया है, और इसलिए एकीकृत आर्थिक पर्यावरण और सामाजिक-जनसांख्यिकीय आँकड़ों के उत्पादन के लिए सांख्यिकीय कार्यालयों के लिए चुनौतियाँ खड़ी की हैं। ऐसे एकीकृत और बहुआयामी आँकड़ों के विकास के लिए प्रासंगिक सांख्यिकी के उत्पादन को एकीकृत करने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है।

2.4 **एकीकृत आर्थिक सांख्यिकी** की प्रेरणा उन लाभों से प्राप्त होती है जो ये आंकड़े समन्वित राष्ट्रीय और वैश्विक नीतिगत उपक्रमों के लिए तेजी से अंतःपरस्पर संबद्ध विश्व में उपलब्ध कराते हैं। यह प्रेरणा सांख्यिकीय प्रणालियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर से स्वतंत्र सभी देशों के लिए प्रासंगिक है। समेकन छोटे और व्यापक राष्ट्रीय आर्थिक आँकड़े समुच्चय हेतु प्राप्त करने योग्य है और इसे उत्तरोत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में शुरू किया जा सकता है।

2.5 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयमें परिवर्तन के लिएविज़न भारतीय संदर्भ के लिए ढांचे को अपनाकर शासकीय सांख्यिकी के आधुनिकीकरण (एम ओ एस) के लिए संयुक्त राष्ट्र ईसीई उच्च-स्तरीय समूह की व्यापक सिफारिशों की तर्ज पर होगा। इस ढांचे में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

क) **सामान्य सांख्यिकीय व्यवसाय प्रक्रिया मॉडल (जी एस बी पी एम)** - यह मॉडल सांख्यिकीय संगठनों द्वारा सांख्यिकीय आउटपुटके उत्पादन हेतु मुख्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। यह संगठनों में अक्षमता और अतिरेक को कम करने वाली सामान्य प्रक्रियाओं का पता लगाने में मदद कर सकता है।

ख) **सामान्य सांख्यिकीय सूचना मॉडल (जी एस आई एम)** - यह मॉडल सांख्यिकीय संगठनों द्वारा सांख्यिकीय निर्गमका उत्पादन करने के लिए आवश्यक जानकारी की मुख्य मदों का वर्णन करता है। यह जीएसबीपीएम प्रक्रियाओं के अंदर और उनके बाहर की जानकारी का वर्णन करने के लिए एक आम भाषा उपलब्ध करवाता है।

ग) **सामान्य सांख्यिकीय उत्पादन वास्तुकला (सी एस पी ए)** - सी एस पी ए सांख्यिकीय नमूनों, कार्यान्वित विधियों और कार्यान्वित सेवाओं, अधिक आसानी से साझा करने और पुन: उपयोग के विधियों हेतु सांख्यिकीय संगठनों के लिए अतिव्यापी ढांचा प्रदान करता है।

घ) **सांख्यिकीय संगठनों के लिए सामान्य गतिविधि मॉडल (जी ए एम एस ओ)** - यह मॉडल एक विशिष्ट सांख्यिकीय संगठन के भीतर होने वाली गतिविधियों का वर्णन करता है। यह सांख्यिकीय उत्पादन का समर्थन करने के लिए आवश्यक व्यापक प्रक्रियाओं को जोड़कर जी एस बी पी एमको विस्तार और पूरक उपलब्ध करवाता है।

परिवर्तनकारी ढांचा, जब कार्यान्वित किया जाएगा, तो यह सांख्यिकीय रजिस्ट्रियों के सॉफ्टसमेकन सहित मेटा-डेटा के माध्यम से सिस्टम में विद्यमान डेटा साइलो के सॉफ्टसमेकन को सुकर बनाएगा।

2.6 इस परिवर्तन के लिए न केवल प्रौद्योगिकीय इंटरवेंशन, बल्कि सांख्यिकीय ढांचे के लिए मानव पूंजी के प्रबंधन की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण स्तंभ है। नए आँकड़ा स्रोतों कालाभ उठाने के लिए नवीन तकनीकों का विकास किया जाएगा और उन्हें अनुसंधान और अन्य संस्थानों की भागीदारी की आवश्यकता होगी ताकि राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में उपयोग के लिए नए विचारों कासार्वजनिकरूप से एकत्रण,समूहन और विकास किया जा सके।

ग. राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली-विज़न 2024

3. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अगुवाई में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के विज़न 2024, का मूल इस तथ्य में है कि शासकीय आँकड़े एक सार्वजनिक वस्तुहैं और विकास के बुनियादी ढांचे

का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रौद्योगिकीय इंटरवेंशनों का उपयोग करके देश में उपलब्ध सांख्यिकीय उत्पादों के लिए अधिआंकड़ों के समन्वय और सामंजस्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विज़न 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार के लिए एक समग्र, सुसंगत और व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे देश में शासकीय आंकड़ों को विश्वसनीय और सतत तरीके से वितरित किया जा सके। इसका उद्देश्य सांख्यिकीय उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के साथ सरकार और अन्य हितधारकों के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर आंकड़े प्रदान करके पहचान किए गए आँकड़ा अंतराल को भी पूरा करना है। सुधार उपायों से वर्तमान व्यवस्था में सामने आ रही संस्थागत, संगठनात्मक और प्रौद्योगिकीय चुनौतियों का समाधान होगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयके पांच साल केविज़नको इस प्रकार परिकल्पित किया गया है:

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय–विज़न 2024
"जनता के लिए योजना और प्रबल प्रसारकार्य हेतु रियल-टाइम इनपुट प्रदान करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली को सदृढकरना।"

घ. राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली - परिवर्तनशील विषय-वस्तु

4.1 राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली उपलब्ध हो रहे आंकड़ों की व्यापक मात्रा तक पहुँचने और एकीकृत करने के नए अवसरों के साथ एक गतिशील वातावरण में काम कर रही है। नीति निर्माताओं द्वारा अर्थव्यवस्था के निष्पादन की निगरानी के लिए आंकड़ों तक वास्तविक समय अभिगम; मिड-कोर्स सुधारों पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए प्रारंभिक संकेतों की पहचान करने तथा इष्टतम तरीकों की पहचान करने और प्रतिक्रिया देने के साधनों को सुविधाजनक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली को अर्थव्यवस्था और समाज की तेजी से बदलती प्रकृति के साथ तालमेल रखने की आवश्यकता है। एक विश्वसनीय सांख्यिकीय प्रणाली को विभिन्न उपयोगकर्ताओं की

आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उच्च गुणवत्ता और समय पर आँकड़े उत्पन्न करने वाली सांख्यिकीय उत्पादन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

4.2 शासकीय सांख्यिकी के लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक स्वतंत्रता के साथ,सांख्यिकी तैयार करने की आवश्यकता, समान रूप से महत्वपूर्ण है। परिवर्तन के दौर से गुजर रहे देशों ने (क) बदलती नीति, कानूनी और शासन व्यवस्थाओं का, जो उनकी सांख्यिकीय प्रणालियों को आकार देते हैं;और(ख) अपने सांख्यिकीय कार्यालयों के संचालन को आधुनिक बनाकर और अपनी तेजी से बदलती अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादित सांख्यिकीय निर्गम के प्रकार को समायोजित करके; अनुकूलन किया है।

4.3 सरकार प्रशासनिक, सर्वेक्षण, संस्थागत और लेनदेन आंकड़ों के विशाल भंडार की संरक्षक है। इस तरह के आंकड़ों को 'प्रशासनिक सांख्यिकी' कहा जाता है, जो अनिवार्य रूप से, एमसीए, जीएसटीएन आदि की तरह, मोटे तौर पर विशिष्ट कानून के प्रबंधन के एक उप-उत्पाद के रूप में,अपने दस्तावेजों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है । विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा एकत्र किए गए प्रशासनिक आंकड़ों का बेहतर ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इस तरह के बहुत से आँकड़ा समुच्चय विभिन्न सरकारी संस्थानों और अभिकरणों में बिखरे पड़े हैं। ये अभिकरण आँकड़ा सिलोस में आंकड़ों के संग्रह और संकलन के लिए कई रजिस्ट्रियाँ भी रखते हैं। सामाजिक कल्याण के प्रत्येक संकेतक के लिए, आंकड़ों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी केंद्र या राज्य सरकार की संस्था के पास होती है और प्रत्येक ने अपने स्वयं के अधिआंकड़ा मानकों को परिभाषित किया है, जहां अधिआंकड़े वह संरचित न्यूनतम जानकारी है जो एक सूचना संसाधन का प्रबंधन या उपयोग, पता लगाना या अन्यथा इसे पुनः प्राप्त करना,वर्णन, व्याख्या करना आसान बनाती है । कुछ ई-गवर्नेंस परियोजनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीटवाई) द्वारा समन्वित अधिआंकड़ों और आंकड़ा मानकों (एमडीडीएस) का अनुसरण करती हैं। हालाँकि, सामान्य तौर पर, एक सरकारी अभिकरण द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को दूसरे द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों से अलग रखा जाता है । मध्य-मार्ग कार्यप्रणाली संशोधन को प्रभावित करने के लिए वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न समुच्चयों और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए आँकड़े समुच्चयों में जानकारी को एकीकृत करना नीति निर्माताओं के

लिए बेहद उपयोगी होगा। इस तरह के एकीकृत आंकड़ें विभिन्न अभिकरणों द्वारा बनाए गए पृथक आँकड़े समुच्चयों की तुलना में अधिक मूल्यवान है।

4.4 ये निर्विवाद आँकड़े समुच्चय बड़ी मात्रा में अनुलिपि आंकड़ें बनाते हैं, आभासी आँकड़ों भंडारण पर दबाव बढ़ाते हैं और संभावित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को रोकते हैं। नीति निर्माताओं को लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के बारे में सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थी योजनाओं में रजिस्ट्रियों का कोई सामान्य आंकड़ा संचय मौजूद नहीं है। इसी प्रकार, वित्तीय क्षेत्र, स्थापना और उद्यमों से संबंधित आंकड़े भी सरकारी संस्थानों में असंबद्ध और बिखरे हुए हैं।

4.5 सिलोस में मौजूद आंकड़ों का समेकन देश के विकसित सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। सूचनाओं को साझा करने और आँकड़े समुच्चयों तक पहुंच को सक्षम करने से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार होगा, लोगों को बेहतर निर्णय लेने और एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक वस्तु का लोकतंत्रीकरण करने में मदद मिलेगी। चूंकि आंकड़ा संचय धीरे-धीरे केंद्र और राज्य सरकारों के भीतर ऑन-लाइन हो गए हैं, वे भविष्य की शासन प्रणाली के लिए ठोस राष्ट्रीय आंकड़ा अव संरचना के निर्माण के लिए एक नया अवसर प्रदान करते हैं। यह डिजिटल और पोर्टेबल स्वरूपों में आँकड़े समुच्चय की अंतर-क्षमता को भी समर्थ बनाएगा।

4.6 आंकड़ा क्रांति के नए अवसरों को अपनाने के लिए, सांख्यिकीय प्रणाली के हर हिस्से में प्रभावी अनुसंधान और विकास तथा नवाचार आवश्यक तत्व हैं। अगले पाँच वर्षों के दौरान, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयका उद्देश्य अभिनव, कुशल और प्रभावी विधियों का उपयोग करते हुए आवश्यक सांख्यिकीय आवश्यकताओं के अनुकूलन के लिए अग्रणी विधियाँ विकसित और लागू करना है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयसरकार के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए प्रशासनिक आँकड़ों के अधिक उपयोग और अनुबंधन प्रयोग की सुविधा प्रदान करेगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय , सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए सरकार के भीतर और बाहर आँकड़ों के साझा करने में एक प्रमुख बदलाव लाने के लिए हितधारकों के साथ अपनी ठोस बातचीत के माध्यम से

नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने तथा तरीकों की पहचान और उनका लाभ उठाने का इरादा रखता है। इसी तरह, उपयोगकर्ता-अनुकूल तरीके से आँकड़ों की जनता तक पहुंच बनाई जाएगी।

4.7 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के लिए बुनियादी अभिकरण के रूप में, डिजिटल तकनीकों का बेहतर उपयोग करके इन आँकड़ाँ सिलोस और उनके विश्लेषिकी, प्रबंधन और प्रसार को एकीकृत करने की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है। चूंकि आँकड़ा प्रणालियाँ उल्लेखनीय समय से संचालन में रही है, अतएव परिचालित प्रणालियों पर मेटाडाटा मानकों का पुनःसंयोजन संभव नहीं है। इस दृष्टिकोण से मेटाडाटा की सॉफ्ट मैपिंग होगी और **डेटा-लेक आर्किटेक्चर** की सुविधा होगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, जो हस्तचालित सिस्टम के माध्यम से संभव नहीं है।

4.8 आँकड़ा-प्रसार का सुदृढ़ीकरण करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूपों में आँकड़ा परिसंपत्तियों के समय पर प्रसार और सांख्यिकी संचार में सुधार दोनों पर जोर दिया जाना आवश्यक है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पहले से ही अपने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के प्रासंगिक अधिआँकड़ों के साथ इकाई स्तर के आँकड़ों तक पहुंच प्रदान कर रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अपने हितधारकों के साथ संचार तंत्र का सुदृढ़ीकरण करने तथा कार्यनीतिक संचार और मार्का प्रबंधन, मीडिया संबंध, सामग्री निर्माण, वेबसाइट प्रबंधन, हितधारक रखना, सामाजिक संचार माध्यम, डिजिटल मीडिया और आँकड़ा प्रत्योक्षकरण में विशेषज्ञता का निर्माण करने की योजना भी है। संचार और उपयोगकर्ता जुड़ाव में, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संकेतकों से संबंधित व्यावहारिक रुझान और अवधारणाओं को उजागर करने के लिए बेहतर सूचना चित्रालेख और चलचित्र, तथा गतिशील प्रत्योक्षकरण के अधिक से अधिक उपयोग द्वारा सुधार किया जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सटीक और सार्थक व्याख्या को प्रोत्साहित करने तथा समझने में आसान आँकड़ों, सांख्यिकी और विश्लेषण को अधिक सुलभ बनाने के अभिनव तरीकों का पता लगाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयके सांख्यिकीय उत्पाद उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता की रक्षा करते हुए पुन: उपयोग के लिए खुले प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।

4.9 उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अगले पांच वर्षों में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपने विज़न को साकार करने के लिए सांख्यिकीय उत्पादों और प्रक्रियाओं के व्यापक सुधार को लागू करेगा। यह सुधार प्रक्रिया निम्नलिखित व्यापक विषयों पर केंद्रित होगी:

विषय I:	अर्थव्यवस्था की रियल-टाइम निगरानी के लिए सांख्यिकीय बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण।
विषय II:	आँकड़ा साझा करने के संलेख और प्रौद्योगिकी के उपयोग को एकीकृत करके एक एकीकृत सूचना संलेख के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में विभिन्न मंत्रालयों में मौजूद आँकड़ों और रजिस्ट्रियों को एकीकृत करना।
विषय III:	बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी का सुदृढ़ीकरण

4.10 सुधारों के विषय भारतीय संदर्भ में अनुकूलन के बाद **यूएन जेनेरिक स्टैटिस्टिकल बिजनेस प्रोसेस नमूना(जीएसबीपीएम), जेनेरिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन नमूना(जीएसआईएम), कॉमन स्टैटिस्टिकल प्रोडक्शन आर्किटेक्चर (सीएसपीए) तथा जेनेरिक एक्टिविटी नमूनाफॉर स्टैटिस्टिकल ऑर्गनाइजेशन (जीएमएसओ)** पर आधारित होंगे, । (ऊपर अनुच्छेद 2.5 संदर्भित करता है)।

## ड.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली - परिवर्तनकारी कार्यनीतियाँ

5.1	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयद्वारा किए जा रहे सांख्यिकीय सुधार उपक्रमों को सरकारी नीतियों और इंटरवेंशनों के लिए आँकड़े प्रदान करने के लिए अग्रणी होकर स्वयं का पुनः स्थितियन करनेहेतुअति महत्वाकांक्षी समय के साथ एक मिशन मोड विज़न के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयने परिष्कृत जीवन निर्वाह सुविधा के साथ और 2024 तक यू एस डी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए सरकार के लक्ष्य की प्रगति को मापने के लिए आँकड़ा चालित इंटरवेंशनों के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख चालकों की पहचान की है। ये चालक निम्नलिखित कार्यनीतियों पर आधारित हैं।

कार्यनीति I:	संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण
कार्यनीति II:	प्रौद्योगिकीय और भौतिक संरचना का सुदृढ़ीकरण
कार्यनीति III:	प्रभावी मानव पूंजी प्रबंधन

5.2	सांख्यिकीय उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए परिवर्तन की प्रेरणा चित्र 5.1में चित्रित **संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय व्यवसाय प्रक्रिया** मॉडल **(जी एस बी पी एम)** होगा। ऐसे 50 से अधिक विकासशील और विकसित देश हैं जिन्होंने राष्ट्रीय कृषि कार्यपद्धतियों में दक्षता और प्रासंगिकता में सुधार के लिए इस नमूने को अन्य परिवर्तनकारी नमूने के साथ संयोजन के रूप अंगीकार में किया है।

चित्र 5.1: संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकीय व्यापार प्रक्रिया नमूना(जी एस बी पी एम)

व्यापक प्रक्रिया							
निर्दिष्ट आवश्यकताएं	अभिकल्पना	निर्माण	एकत्र	प्रक्रिया	विश्लेषण	प्रसार	मूल्यांकन
1.1 आवश्यकताओं की पहचान करें	2.1 निर्गम की अभिकल्पना करें	3.1 संग्रह उपकरणों का पुन: उपयोग या निर्माण करें	4.1 फ्रेम बनाएं और नमूना चुनें	5.1 डेटा को एकीकृत करें	6.1 ड्राफ्ट आउटपुट तैयार करें	7.1 आउटपुट सिस्टम अपडेट करें	8.1 मूल्यांकन जानकारी इकट्ठा करें
1.2 परामर्श और आवश्यकताओं की पुष्टि	2.2 संस्करण विवरण अभिकल्पना	3.2 प्रक्रियाओं और विश्लेषण के घटकों का पुन: उपयोग या निर्माण करें	4.2 संग्रह स्थापित करें	5.2 वर्गीकृत और संहिता कोड	6.2 आउटपुट मान्य करें	7.2 प्रसार उत्पादों का उत्पादन करें	8.2 मूल्यांकन संचालन
1.3 निर्गम उद्देश्य स्थापित करें	2.3 संग्रह अभिकल्पना	3.3 प्रचार-प्रसार घटकों का पुन: उपयोग या निर्माण करें	4.3 संग्रह चलाना	5.3 समीक्षा करें और मान्य करें	6.3 व्याख्या और सवालों का जवाब दें	7.3 प्रसार उत्पादों को जारी करने का प्रबंधन करें	8.3 एक कार्य योजना पर सहमत
1.4 अवधारणा की पहचान करें	2.4 फ्रेम और नमूना अभिकल्पना	3.4 कार्यप्रवाह को विन्यस्त करें	4.4अंतिम संकलन	5.4 आगम और संपादित करें	6.4 प्रकटीकरण नियंत्रण लागू करें	7.4 वितरण उत्पादों की को बढ़ावा देना	
1.5आंकड़ा उपलब्धता की जांच करें	2.5 प्रक्रिया और विश्लेषण अभिकल्पना	3.5 उत्पादन प्रणाली जाँच		5.5 नए चर और इकाइयों को प्राप्त करें	6.5 अंतिम निर्गम	7.5 प्रबंध उपयोगकर्ता समर्थन	
1.6 व्यवसाय का मामला तैयार करें और प्रस्तुत करें	2.6 उत्पादन प्रणाली और कार्यप्रवाह अभिकल्पना	3.6 सांख्यिकीय व्यवसाय प्रक्रिया जाँच		5.6 भार की गणना करें			
		3.7 उत्पादन प्रणालियों को अंतिम रूप		5.7 औसत की गणना करें			
				5.8 डेटा फ़ाइलों को अंतिम रूप दें			

5.3 उपरोक्त जीएसबीपीएम मॉडल जैसा कि नीचे चित्र 5.2 में दिखाया गया है, को भारतीय अर्थव्यवस्था के **वास्तविक समय निगरानी** के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय परिदृश्य को बदलने के लिए भारतीय संदर्भ में अनुकूलित किया जा सकता है। इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि मंत्रालय ने पहले ही जीएसबीपीएममॉडल के तहत कई कदम उठाए हैं, हालांकि यह एक अलग तरीके से है और विभाग विशिष्ट गतिविधियों तक ही सीमित है। अब प्रयास यह होगा कि इस मॉडल को एक ढांचे के रूप में उपयोग करते हुए वैश्विक सर्वोत्तम कार्यपद्धतियाँ के अनुरूप परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं को लाया जाए।

चित्र 5.2: भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक समय निगरानी के लिए एकीकृत आँकड़े

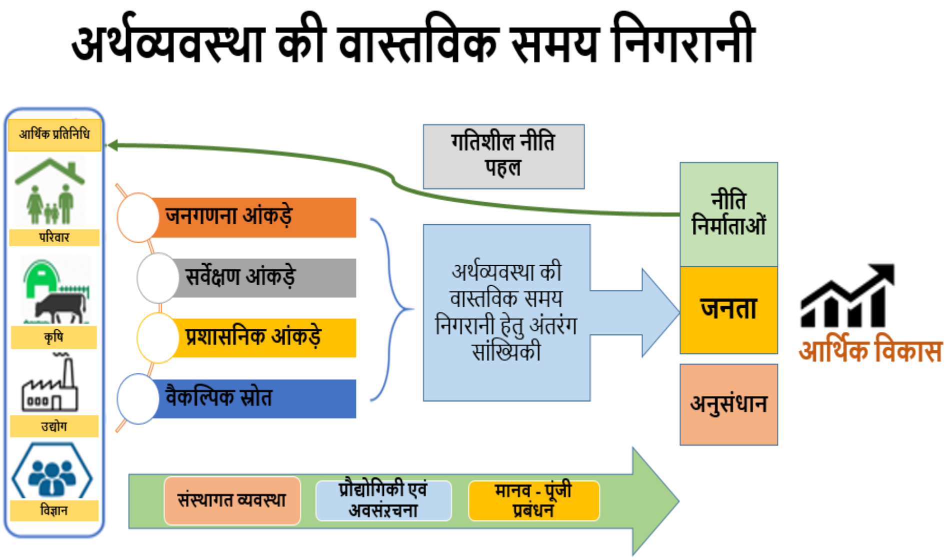

5.4 यह देखा जा सकता है कि परिवर्तन का जोर केवल जनगणना, सर्वेक्षणों और प्रशासनिक आंकड़ों में सुधार की गई सांख्यिकीय कार्यपद्धतियाँ पर केंद्रित नहीं है, जो सांख्यिकीय जानकारी के पारंपरिक स्रोत हैं। वास्तव में, बिग डाटासे निकलने वाले **नए / वैकल्पिक आँकड़ा स्रोतों** की लागत कम होने की संभावना है और ये अधिक समयोचित और बीजमय सांख्यिकी में परिणत हो सकते हैं। हालांकि, अभी भी ऐसे मुद्दे हैं जो इस तरह के आँकड़ो के उपयोग में बाधा डालते हैं, जैसे कि संभाव्य पूर्वाग्रह, विस्तृत सूचना, उपयोगकर्ता-जनित सामग्रियों की सटीकता के बारे में अनिश्चितता, आँकड़ाधारकों के साथ

समन्वय की कठिनाई, गोपनीयता नियम और सामाजिक लाइसेंस। इन्हें एक प्रभावी नीतिगत ढांचे के माध्यम से दूर करने की आवश्यकता है।

च. राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली – कार्यान्वयन विज़न

6.1 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विजन 2024 को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन ढांचे में संस्थागत, कानूनी और नीतिगत ढांचे सहित परिवर्तन के महत्वपूर्ण संचालक को जुटाना, आईटी कार्यनीति, मानव पूंजी प्रबंधन, गुणवत्ता चेतना, नवाचार और आरएंडडी और उपयुक्त विघटन कार्यनीति सहित उपयोगकर्ता की सहभागिता बढ़ाना शामिल होगा।

कार्यनीति I: संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण

6.2 विगत में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा डॉ. सी. रंगराजन (2000-2001) के नेतृत्व में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार के लिए कई पहल कीगईं थीं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सांख्यिकीय मामलों पर एक सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एन एस सी) की स्थापना, सांख्यिकी अधिनियम, 2008 का संग्रह, राष्ट्रीय खातों के क्षेत्र में आँकड़ा संग्रह और प्रसारके अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना, मूल्य आँकड़े, औद्योगिक सांख्यिकी, **सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी)** की निगरानी के लिए **राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ)** की अभिकल्पना, बड़े पैमाने पर केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्वयं के सांख्यिकीय उत्पादों को विकसित करने में प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करना, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता, शासकीय सांख्यिकी में क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं। भारत ने **शासकीय सांख्यिकी के संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों (यूएनएफपीओएस)** को

भी अंगीकार किया है, जो सरकारी आँकड़ों को सार्वजनिक वस्तु के रूप में मान्यता देते हैं, जिन्हें कुछ बुनियादी सिद्धांतों जैसे संकलन, संग्रह और प्रसार के विधियों के बारे में पारदर्शिता तथा व्यावसायिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता, जवाबदेही का पालन करने की आवश्यकता होती है।

6.3 भारत में सांख्यिकीय अभिकरणों द्वारा अपनी प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों के बावजूद कुछ निश्चित प्रणालीगत कमियाँ, आवश्यक जानकारी की उपलब्धता में अंतराल का अस्तित्व; परिणामों के प्रकाशन में देरी; जारी संकेतकों के आवधिक संशोधन; विभिन्न स्रोतों से शासकीय आंकड़ों के बीच विसंगतियां; सांख्यिकीय संचालन में पारदर्शिता; प्रशिक्षित जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, के रूप में बनी रहती हैं। इन कमियों का विकेंद्रीकृत प्रणाली में विशेषत: सांख्यिकीय आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता है। मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और कानूनी ढांचे को आंकड़ों की बढ़ती आवश्यकताओं के साथ और वास्तविक समय आधार पर अर्थव्यवस्था के मिज़ाज की निगरानी के लिए सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस दिशा में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयका उद्देश्य मौजूदा संस्थागत, कानूनी और नीतिगत ढांचे में परिवर्तनकारी उपाय करके शासकीय सांख्यिकीय प्रणाली को और मजबूत करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वसनीय शासकीय आँकड़ों तक पहुँच न्यायसंगत और निर्बाध हो और यह आर्थिक विकास एजेंडाके लिए शासकीय आँकड़ों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देती हो।

I. क शासकीय सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति

6.4 भारत सरकार ने देश में शासकीय सांख्यिकी के उत्पादन और प्रसार में अच्छे कार्यो और पेशेवर नैतिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में **संयुक्त राष्ट्र मौलिक सिद्धांतों** को अंगीकार किया। इन सिद्धांतों से आशा की जाती है कि ये निर्णय निर्माताओं, सांख्यिकीविदों, आंकड़ां प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न तरीकों से लाभान्वित करने और शासकीय सांख्यिकीय प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास पैदा करने तथा नागरिकों और उपयोगकर्ताओं में 'सार्वजनिक वस्तु ' स्वरूप पात्रता

को सम्मान मिलने की उम्मीद है। इन सिद्धांतों के आगे, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय **शासकीय सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय नीति (एन पी ओ एस)** तैयार कर रहा है, जो सांख्यिकीय मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिक तालमेल लाने के लिए एक बेहतर सांख्यिकीय प्रणाली की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगी। यह लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सूचित बहस के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन देने और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, और समय पर और विश्वसनीय सामाजिक और आर्थिक आंकड़ें प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

I. ख राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का सुदृढीकरण

6.5 वर्ष 2001 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सिफारिशों के अनुपालन मेंसरकार ने दिनांक 1 जून, 2005; के संकल्प द्वारा सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार करने और इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त क़ानून विकसित करने के लिए, एक जनादेश के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एन एस सी) का गठन किया। एनएससी को अपनी स्वयं के प्रक्रिया संबंधी अनुभव के मद्देनजर एक क़ानून विकसित करना था और मुख्य आँकड़ों (राष्ट्रीय महत्व के आँकड़ों) की पहचान करनी थी जहाँ सरकार के संसाधनों को प्राथमिकता दी जा सके। हालांकि, एनएससी ने अपनी स्थापना के बाद से अपने वार्षिक प्रतिवेदनके माध्यम से सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार करने के लिए कई सिफारिशें की हैं, फिर भी, प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन ज्यादातर अपरिचित बने रहे। एनएससी का जनादेश दूरगामी है और इसके लिए अपनी कार्यपद्धतियाँ को प्रभावी ढंग से करने के लिए, उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए इसे उपयुक्त पेशेवर स्वायत्तता के साथ उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब शासकीय सांख्यिकीय प्रणाली एक प्रतिमान बदलाव के दौर से गुजर रही है, तो यह काफी महत्व रखता है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली कीकार्यपद्धति में एक समान परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है, जिसमें सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयभी शामिल है।

I. ग सर्वश्रेष्ठ वैश्विक कार्य पद्धतियाँ को अंगीकार करना

6.6 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित क्षेत्रों में सांख्यिकीय संचालन और सेवाओं में **संयुक्त राष्ट्र सामान्य सांख्यिकीय व्यवसाय प्रक्रिया मॉडल (जी एस बी पी एम)** (चित्र4.1) के ढांचे का लाभ उठाएगा:

क) एक सुसंगत और समझने योग्य तरीके से सांख्यिकीय प्रक्रियाओं को परिभाषित और वर्णित करना;

ख) सांख्यिकीय अभिकरणों या संगठनों के भीतर और मध्य की प्रक्रियाओं की तुलना और मानदण्ड प्रक्रिया हेतु;

ग) सांख्यिकीय उत्पादन प्रणालियों और उपलब्ध संसाधनों के संगठन पर बेहतर निर्णय लेने के लिए।

6.7 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयका मानना है कि जी एस बी पी एम एक रैखिय मॉडल नहीं है और उप-प्रक्रियाओं को विशुद्ध अनुक्रम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, जीएसबीपीएम को स्वीकार करते समय, इसे एक प्रक्रिया मैट्रिक्स माना जाएगा, जिसके माध्यम से फेज़ के भीतर और मध्य चलने वाले छोरों सहित कई संभावित वैकल्पिक मार्ग हैं, जिन्हें पहचाना और प्राथमिकता दी जाएगी। जी एस बी पी एममें विभिन्न घटकों की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन शामिल होगा।

6.8 संक्षेप में, **कार्यनीति I** के तहत उठाए जाने वाले प्रमुख कदम हैं:

क) शासकीय सांख्यिकी के संयुक्त राष्ट्र मौलिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए **शासकीय सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय नीति** का प्रारूपण और अंतिम रूप देना।

ख) **राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग** को केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग, शिक्षा और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी तथा व्यापक परामर्श के माध्यम से मजबूत करना।

ग) सांख्यिकीय संचालन और सेवाओं में **जेनेरिक सांख्यिकीय व्यापार प्रक्रिया मॉडल (जी एस बी पी एम)** के संचालन के लिए एक सांख्यिकीय ढांचे की स्थापना करना। इसमें

सांख्यिकीय प्रक्रियाओं, सांख्यिकीय आंकड़ा संचय का समेकन और बहु-विषयक अवधारणाओं और परिभाषाओं का अभिसरण शामिल होगा।

घ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयमें एक चुस्त संस्थागत ढांचे की स्थापना करना जो नवाचार, समूहित और नए विचारों और प्रक्रियाओं के विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके लिए मंत्रालय के भीतर आंतरिक पुनर्गठन की आवश्यकता है ताकि विभिन्न प्रभाग प्रक्रिया और उत्पाद सुधारों के माध्यम से अधिक सामंजस्यपूर्ण और कुशल हो जाएं।

ड.) सांख्यिकीय संचालन में उत्कृष्टता के संस्थानों के साथ कार्यनीतिक साझेदारी और सहक्रियाओं की स्थापना और विशेष रूप से एसडीजी के लिए आँकड़े की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों का लाभ उठाना।

कार्यनीति II: प्रौद्योगिकीय और भौतिक संरचना का सुदृढ़ीकरण

7.1 सांख्यिकीय प्रणाली प्रक्रियाओं में सुधार उत्पादों में नवीनतम तकनीकों को अपनाने के साथ आंतरिक रूप से जुड़े है ताकि अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए सिस्टम की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयने हाल ही में आँकड़े-एकत्रीकरण, भंडारण, प्रसंस्करण और सांख्यिकीय जानकारी के प्रसार में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर कई आईटी पहल की हैं। हालाँकि, बहुत कुछ किया जाना बाकी है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकीय प्रगति का प्रयोग करना और उसे अंगीकार करना और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अगले पांच वर्षों के दौरान इन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध है।

7.2 राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली विरासत प्रणालियों, डाटा साइलो और डिजिटल परिवर्तन को प्रदान करने की क्षमता में कमी के साथ सतत जूझती आई है। सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में, तत्काल प्राथमिकता वास्तविक समय की निगरानी करना और व्यापक आर्थिक संकेतकों की उपलब्धता के लिए इन आँकड़े समुच्चयों को एकीकृत करके एक जगह पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों में उपलब्ध होने वाले सामाजिक-आर्थिक आँकड़े उपलब्ध कराना है। इसमें आवश्यक रूप से एजेंसियों के बीच

आँकड़े साझा करने संबंधी प्रोटोकॉल और मानकों को विकास करना शामिल होगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आईटी हस्तक्षेपों को नियंत्रित करने वाले व्यापक सिद्धांतों **जेनेरिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मॉडल (जी एस आई एम)** में स्थिरक है, जो सांख्यिकीय व्यापार प्रक्रिया के भीतर सूचना वस्तुओं और प्रवाह का वर्णन करता है, और **कॉमन स्टैटिस्टिकल प्रोडक्शन आर्किटेक्चर (सी एस पी ए)** जिससे प्रत्येक संगठन के लिए सांख्यिकीय उत्पादन के घटकों को मानकीकृत और संयोजित करना आसान हो जाएगा, चाहे वे सांख्यिकीय सेवाएँ कहीं से भी ली जाएँ। आँकड़े विनिमय के लिए प्रोटोकॉल विभिन्न आँकड़े सिस्टमों में यथाआवश्यक के रूप में **एसडीएमएक्स** और आँकड़े डॉक्यूमेंटेशन इनिशिएटिव पहल **(डीडीआई)** का उपयोग करेंगे।

II.क सांख्यिकीय उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

7.3 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नेदेश में शासकीय आंकड़ों के लिए एक राष्ट्रीय **एकीकृत सूचना पोर्टल (एन आई आई पी)** विकसित करने की प्रक्रिया में है। एन आई आई पीएकरूप मेटा-डेटा के साथ सभी शासकीय आँकड़ों का अत्याधुनिक डिजिटल भंडार होगा। एनआईआईपी आँकड़े एनालिटिक्स के लिए हाई एंड प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा और केंद्रीय मंत्रालयों / राज्य सरकारों और सामान्य लोगों सहित अन्य हितधारकों को सामाजिक-आर्थिक आँकड़े की व्याख्या करेगा। यह वास्तविक समय की निगरानी और स्थूल -आर्थिक संकेतकों की नाउ-कास्टिंग के लिए सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के लिए एक डैशबोर्ड भी होगा।

7.4 एन आई आई पी के विकास में तीन चरण शामिल हैं। पहले चरण में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयकी सभी सांख्यिकीय गतिविधियों को एकीकृत किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों / एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रमुख आँकड़े समुच्चयों को आँकड़े के साझा प्रवाह के लिए प्रौद्योगिकीय समाधानों का उपयोग करके एकीकृत किया जाएगा। तीसरे चरण में, राज्य सरकार की एजेंसियों में उपलब्ध आँकड़े एनआईआईपी पर ऑन-बोर्ड किया जाएगा। अंतिम चरण में, एनआईआईपी को वास्तविक समय आधार पर अर्थव्यवस्था के मिजाज और प्रगति पर नजर रखने और

डेटा एनालिटिक्स के आधार पर सेक्टर विशिष्ट हस्तक्षेपों के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से चालू किया जाना है। एन आई आई पी सतत विकास लक्ष्योंके लिए सूचना के प्रवाह और प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटर की त्वरित पीढ़ी के लिए भी सुविधा प्रदान करेगा ।

II.ख. सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

7.5 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की एक संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर आँकड़े अंतराल को पाटने के लिए नियमित आधार पर इस तरह के सर्वेक्षणों की मांग में तेजी देखी गई है, इससे मौजूदा प्रणालियों पर आँकड़े के गुणवत्ता से समझौता किए बिना सर्वेक्षण के परिणामों को वितरित करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पारंपरिक रूप से कागज़ सूचीपत्र बनाने का उपयोग क्षेत्र -घरों और प्रतिष्ठानों से जानकारी एकत्र करने के लिए करता रहा है। कागज़ आधारित सर्वेक्षण पद्धति में ज्यादातर आँकड़े आधारित आँकड़े प्रोसेसिंग, आँकड़े संवीक्षा आदि शामिल हैं जो परिणामों के समय पर निर्गमन पर एक व्यापक प्रभाव डालते हैं। मंत्रालय ने पहले समय-समय पर जारी आवधिक श्रम सर्वेक्षण के लिए कंप्यूटर एडेड पर्सनल इंटरव्यू (सी ए पी आई) भाग पेश किया था। सीएपीआई सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म आई टी समाधानों का उपयोग करते हुए बुद्धिमान, सरल और कुशल तरीके से पेपर एडेड पर्सनल इंटरव्यू (PAPI) सिस्टम से निर्बाध अवस्थांतर को सक्षम बनाता है। यह सर्वेक्षण प्रबंधन उपकरणों के समुच्चय के माध्यम से सर्वेक्षण संचालन के प्रभावी प्रबंधन जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार (मामलों) के प्रबंधन, आँकड़े स्थानांतरण और साक्षात्कार (मामलों) के आँकड़े निर्यात को एक मानक प्रारूप में प्रस्तुत करता है। मंत्रालय अपने सभी सामाजिक-आर्थिक घरेलू और स्थापना सर्वेक्षणों के लिए एक इन-हाउस सीएपीआई भाग विकसित करने का इरादा रखता है। यह क्षेत्र स्तर पर डिजिटल मोड में त्वरित आँकड़े कैप्चर करना सक्षम बनाएगा, जिससे समय अंतराल कम होगा और पैरा डेटा के विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्र के संचालन की बेहतर निगरानी की सुविधा होगी।

II.ग.   प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का वास्तुशिल्पीय सुदृढ़ीकरण

7.6   इन सुधारों के लिए सामान्य संरचना और पटलों को नीचे चित्र 6.1 में चित्रित किया गया है, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित वैश्विक मॉडल और दिशा-निर्देशों का उपयोग करके परिवर्तनकारी विज़न की व्याख्या करता है।

आकृति 7.1: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयमें व्यापारिक और प्रौद्योगिकीय समेकन

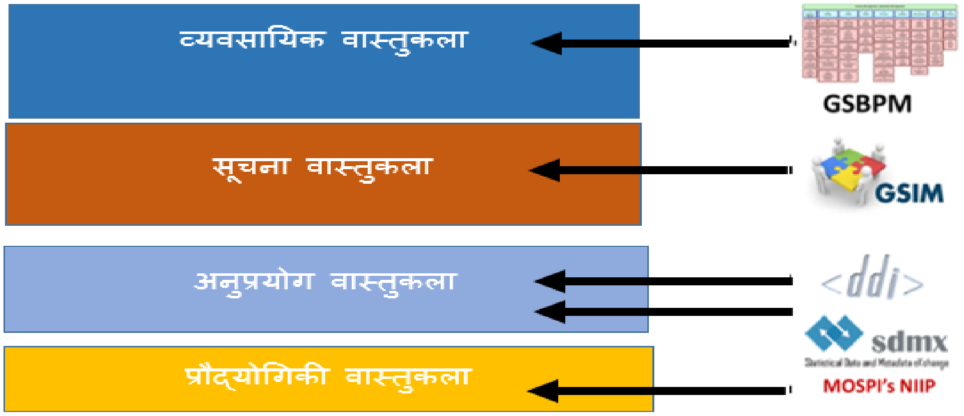

II.घ   पंजीयनों का समन्वित समेकन

7.7   जैसा कि पहले बतायागया था, विभिन्न सरकारी और सांख्यिकीय एजेंसियां अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं और योजनाओं की निगरानी के लिए पंजीयन बनाती हैं। एकीकृत आँकड़ों के उत्पादन के लिए ऐसी पंजीयनों में सूचनाओं के प्रवाह को सुगम बनाने की आवश्यकता है। एक वैचारिक मॉडल चित्र 6.2 में दिया गया है।

आकृति 7.2: पंजियों में समन्वित सूचना प्रवाह

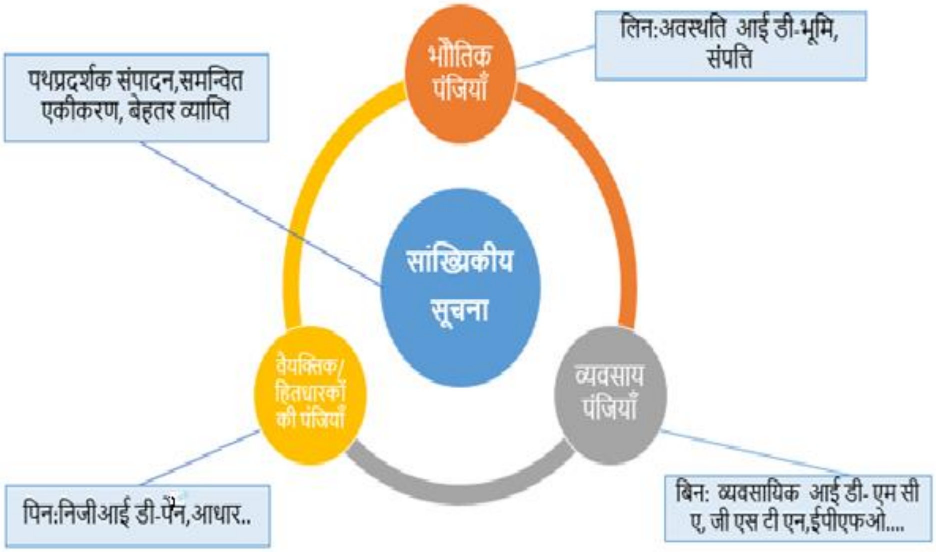

7.8 मौजूदा पंजीयनों में सुधार के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही ऐसे नए निर्माण भी हैं जो अस्तित्व में नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अलग-अलग व्यक्तियों की पंजीयनों के लिए कई मंच उपलब्ध हैं विशिष्ट पहचान (आधार), स्थायी खाता संख्या (पैन), आदि जैसे, औरदो समुच्चयों के समेकन और उन्हें लिंक करने के लिए प्रयास जारी हैं। इसी तरह, ड्रोन और हाई रिज़ॉल्यूशन इमेजनरीका उपयोग करके भौगोलिक इलाके की मैपिंग के लिए भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए इस तरह की पंजीयनों की समग्र जानकारी की जांच करने की आवश्यकता है। इसके लिए गोपनीयता और सुरक्षा की सोच पर समझौता किए बिना सूचना के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच गहन समन्वय की आवश्यकता होगी। इस सॉफ्ट इंटीग्रेशन को एनआईआईपी आर्किटेक्चर के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

यूज़केस - राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यापार रजिस्टर

7.9 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 7वीं आर्थिक जनगणना कर रहा है जो देश के सभी प्रतिष्ठानों / उद्यमों को सूचीबद्ध करती है। आर्थिक जनगणना गतिशील राष्ट्रीय व्यापार रजिस्टर के लिए एक ढांचा प्रदान करेगी जिसे एमसीए, जीएसटीएन, ईएसआईसी, ईपीएफओ आदि के साथ उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करके अपडेट किया जा सकता है। कई राज्य सरकारों ने सभी प्रतिष्ठानों को एकीकृत करके अपना स्वयं का व्यवसाय रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। उदाहरण के लिए, राजस्थान विशिष्ट व्यावसायिक पंजीकरण संख्या (बीआरएन) के साथ व्यापार रजिस्टर विकसित करने में सफल रहा है, जिससे उस राज्य में व्यावसायिक प्रतिष्ठान एकीकृत हो गए हैं। इन सफल उपयोग के मामलों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक जनगणना के माध्यम से उत्पन्न **राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय** रजिस्टर देश में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों / उद्यमों के आँकड़ेबेस के समेकन के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है। सारांश में, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के साथ-साथ प्रतिष्ठानों और उद्यमों का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के एक सामान्य आँकड़े बेस का निर्माण सिस्टम की दक्षता में सुधार के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।

7.10 मंत्रालय ने बड़े केंद्रीय क्षेत्र की 150 करोड़ या उससे अधिक रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समय और लागत बढ़ जाने वालीप्रगति की समीक्षा की। वर्तमान में 1600 से अधिक परियोजनाएं हैं जिनकी मासिक आधार पर निगरानी की जा रही है। निगरानी में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि सरकार उन परियोजनाओं की पहचान कर सके जो त्वरित पूरा होने की क्षमता रखती हैं और तदनुसार निवेश को प्राथमिकता देती हैं।

II. ड. भौतिक संरचना

7.11 वर्तमान में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयदिल्ली भर में फैले हुए छह अलग-अलग स्थानों से कार्य कर रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयकी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों जैसे सकल घरेलू उत्पाद,आईआईपी, सीपीआईइत्यादि को प्रकाशित करने के लिए राज्य सरकारों और मंत्रालय के भीतर , पद मंत्रालयों के मध्य निरंतर समन्वय और सहभागिता की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान स्थापना में तेजी से कठिन होता जा रहा है और इसका मंत्रालय के परिचालन मुद्दों और कामकाज परप्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बढ़ी हुई दक्षता और तालमेल के साथ अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए तथा मंत्रालय के विभिन्न सांख्यिकीय और समन्वय गतिविधियों को तेज करने हेतु एक एकीकृत भवन परिसर की खरीद के लिए प्रारंभिक कदम उठाए हैं।

7.12 इस कार्यनीति के तहत की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) सूचना प्रणालियों के समेकन के लिए अंतर-मंत्रालय समन्वय समिति।

ख) अंतर्निहित प्रौद्योगिकीय पहल के रूप में राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पोर्टल परियोजना का विकास।

ग) राष्ट्रीय मॉडल सर्वेक्षण के लिए एक सामान्यीकृत सर्वेक्षण समाधान का विकास।

घ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयके लिए बुनियादी कार्यालय ढांचे की खरीद।

कार्यनीति III: प्रभावी मानव पूंजी प्रबंधन

8.1 क्षमता निर्माण के संदर्भ में आँकड़े की मांग राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी हैं। हालांकि, डेटा क्रांति शीघ्रता से अधिक और बेहतर आँकड़े के उत्पादन के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करती है,जबकि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के लाभों को प्राप्त करने के लिए, क्षमता वृद्धि एक साथ होनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर सांख्यिकीय प्रणाली को विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और संख्याओं के साथ-साथ कौशल समुच्चय प्राथमिकता के आधार पर संवर्धित करने की आवश्यकता है, ताकि मौजूदा और परिकल्पित भूमिका का निर्वाह किया जा सके। बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग आदि जैसे उपकरणों के आगमन को मौजूदा मानव शक्ति संसाधनों की क्षमता को विकसित करने के लिए एक व्यापक मानव पूंजी प्रबंधन कार्यनीति के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है।

8.2 सिस्टम को लोग बदलते हैं। सरकारों की सांख्यिकीय इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को नए कौशल समुच्चय विकसित करने की आवश्यकता होती है जो उन्हें नई तकनीकों का उपयोग करने, जटिल सांख्यिकीय पद्धतियों को लागू करने, जटिल नीति मुद्दों को समझने और प्रभावी ढंग से संवाद करने और बातचीत सक्षम बनाते हैं। व्यापक क्षमता विकास कार्यक्रमों के अलावा, नियमित और संरचित उपयोगकर्ता-निर्माता संवादों के माध्यम से प्रौद्योगिकीय क्षमता निर्माण का हिस्सा पूरा किया जा सकता है।

8.3 जहां तक मौजूदा सांख्यिकीय जनशक्ति के प्रशिक्षण का संबंध है, ग्रेटर नोएडा में समर्पित राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एन एस एस टी ए) द्वारा इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। अकादमी की भूमिका मुख्य रूप से केंद्र सरकार के सांख्यिकीय संवर्गों और केंद्र और राज्य सरकारों के सांख्यिकीय कर्मियों के लिए सेवा-अल्पकालिक रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण

कार्यक्रम-बद्ध है। शासकीय सांख्यिकी में थोड़े से राज्यों में भी कुछ प्रशिक्षण क्षमताएं मौजूद हैं, लेकिन ये ज्यादातर अपर्याप्त हैं।

8.4 अधिक मात्रा में राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणों की मांग बढ़ रही है और राष्ट्रीय मॉडल सर्वेक्षण (एनएसएस) जहाँ प्रथानुसार प्रत्येक वर्ष केवल एक सर्वेक्षण कर रहा था उसे अब प्रत्येक वर्ष 4-5 नए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है । नए सर्वेक्षणों के बढ़ते कार्यभार को संभालने के लिए नियमित कर्मचारियों को रातोंरात नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए क्षेत्र कार्यके बहि:स्रोतन की कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, एनएसएस ने सर्वेक्षण करने वाले कर्मचारी प्रदान करने के लिए जनशक्ति एजेंसियों को नियुक्त किया, जिन्हें तब फील्ड में तैनात किए जाने से पहले संस्थानिक प्रशिक्षिण दिया गया था। क्षेत्र की निगरानी और पर्यवेक्षण नियमित सांख्यिकीय जनशक्ति द्वारा किया जाता है। त्वरित आँकड़े प्रसंस्करण की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों / टैबलेट पर आँकड़े संग्रह के लिए अब प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, राज्य सरकारों के पास संविदात्मक आधार पर सांख्यिकीय जनशक्ति को संलग्न करने के लिए लचीलापन नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उनके राज्य सर्वेक्षण प्रभावित होते हैं, ये हस्तक्षेप राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं।

8.5 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयने 2019 के दौरान सभी प्रतिष्ठानों की आर्थिक जनगणना का संचालन करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सार्वजनिक सेवा केंद्रों के साथ मिलकर फील्ड वर्क किया है। फील्ड संचालन शुरू होने से पहले इसके लिए गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता थी और इस विज़न को अपनाना संभव था क्योंकि मांगी जा रही जानकारी सीमित रही है। एक विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए, अधिक योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति संसाधनों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, नियमित और संविदात्मक जनशक्ति संसाधनों के संयोजन का उपयोग करके अतिरिक्त सर्वेक्षण करने के लिए एक संकरविज़न को अपनाने की आवश्यकता होगी।

8.6 आधुनिक और विकेंद्रीकृत सांख्यिकीय प्रणाली की वर्तमान और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए, मानव पूंजी प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण और गतिशील बनाने की आवश्यकता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयने राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के लिए मानव पूंजी प्रबंधन कार्यपद्धतियाँ की एक व्यापक समीक्षा करने की योजना बनाई है। अन्य बातों के अलावा, यह समीक्षा मानव संसाधन क्षमताओं का आकलन, भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन, अंतराल विश्लेषण आयोजित करने और इस अंतराल को बंद करने के लिए कार्यनीति का सुझाव देगी। अल्पकालिक के साथ-साथ दीर्घकाल में मानव विकास गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक दिशानिर्देश और एक कार्य-योजना तैयार की जाएगी। सतत विकास के लिए आँकड़े क्रांति ने शासकीय सांख्यिकी के लिए बिगडेटा, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में रुचि पैदा की है। इसकी क्षमता को पहचानते हुए, दुनिया भर के देशों ने वास्तविक-समय सूचना उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए अपनी सांख्यिकीय प्रणाली में इन उभरते विश्लेषणात्मक उपकरणों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। शासकीय सांख्यिकीय प्रणाली में इन आधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करने के लिए, मौजूदा मानव संसाधनों में अपेक्षित कौशल डालने की आवश्यकता है। इसलिए, अगले पांच वर्षों के दौरान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयकी सुधार गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बदलती मांगों पर प्रतिक्रिया देने के लिए मानव संसाधनों की क्षमता और कौशल को बढ़ाना है।

8.7 एन एस एस टी एमानव पूंजी प्रबंधन के लिए केंद्र बिंदु होगा और देश में शासकीय सांख्यिकी में एक **उत्कृष्टता केंद्र** के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए विज़न 2024 में परिकल्पित, अपनी बढ़ी हुई भूमिका को पूरा करने के लिए प्रादेशिक क्षेत्रों में एन एस एस टी एके पदचिहन का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। यह अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरते हुए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विश्लेषणात्मक कौशल के साथ वैश्विक सर्वोत्तम कार्यपद्धतियाँ में प्रशिक्षण और पेशेवरों को तैयार करने के लिए सहयोग करेगा । एनएसएसटीए शासकीय सांख्यिकी में परामर्श / अनुसंधान / अभिनव सेवाएं प्रदान करने के लिए पेशेवरों का एक

निकाय भी बनाएगा। यह सभी संस्थानों में स्नातक स्तर पर अनिवार्य किए जाने के लिए शासकीय सांख्यिकी पर उचित पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम और ई-अधिगम भाग तैयार करेगा। सिविल सेवा में सेवा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों / अकादमियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में प्रशासनिक सांख्यिकी को पेश करने की व्यवहार्यता की जांच की जाएगी।

8.8 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयसर्वेक्षण सामग्री, क्षेत्र निरीक्षण, पर्यवेक्षकों और आँकड़े गुणवत्ता कर्मियों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ भी बातचीत कर रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे सर्वेक्षण प्रगणकों के लिए बाजार को खोलना और विकसित करना है जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सर्वेक्षण करने के लिए पेशेवर एजेंसियों और जनशक्ति सलाहकारों द्वारा काम पर रखा जा सकता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम सेटअप के तहत विकसित क्षेत्रक कौशल परिषद केढांचे का उपयोग करते हुए पाठ्यक्रम सामग्री, मूल्यांकन, मूल्यांकन और प्रमाणीकरण के लिए तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।

8.9 इस कार्यनीति के तहत की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन अधिगम सहित समकालीन सांख्यिकीय तकनीकों और विधियों पर सांख्यिकीय कर्मियों का बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण।

ख) अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों के संपर्क सहित सांख्यिकीय जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी में क्षमता बढ़ाना।

ग) वृद्धि एवं संवर्धन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में सांख्यिकीय क्षमताओं का आकलन करना।

घ) केंद्र सरकार के स्तर पर सांख्यिकीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सांख्यिकीय सेवा और अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा की संवर्ग समीक्षा।

ड.) सर्वेक्षण गणनाकारों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सर्वेक्षण क्षमताओं को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए एमएसडीई कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा चलाए जाने वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को अंतिम रूप देना औरउन्हें आरम्भ करना।

च) केंद्र और राज्य सरकार के सांख्यिकीय संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुशल सर्वेक्षण प्रगणकों के साथ जनशक्ति एजेंसियों को सूची में शामिल करना।

छ. संशोधित राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली - अपेक्षित परिणाम

9.1 संशोधित प्रणाली के व्यापक परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) बेहतर सांख्यिकीय प्रक्रियाएं और उत्पाद निम्नानुसार होने चाहिए :

- सुसंगत
- सटीक
- विश्वसनीय
- यथासमय/ समयानुकूल
- सुलभ
- स्पष्ट
- तुलनीय - स्थानिक, सामयिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

ख) न्यूनतम अतिरेक के साथ बेहतर आँकड़े समेकन

ग) बहु-विषयक सांख्यिकीय उत्पाद

घ) सांख्यिकीय उत्पादों के हितधारकों के बीच साझेदारी और गहन सहयोग

ड.) बेहतर उपयोगकर्ता-निर्माता चर्चा और प्रसार मंच।

इसे विज़न डॉक्यूमेंट में प्रस्तावित परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं द्वारा सुगम बनाया जाएगा और यह नीचे दिए गए चित्र 9.1 में दिखाया गया है:

चित्र 9.1: एकीकृत सांख्यिकी दृष्टिकोण के लिए वास्तुकला ढांचा

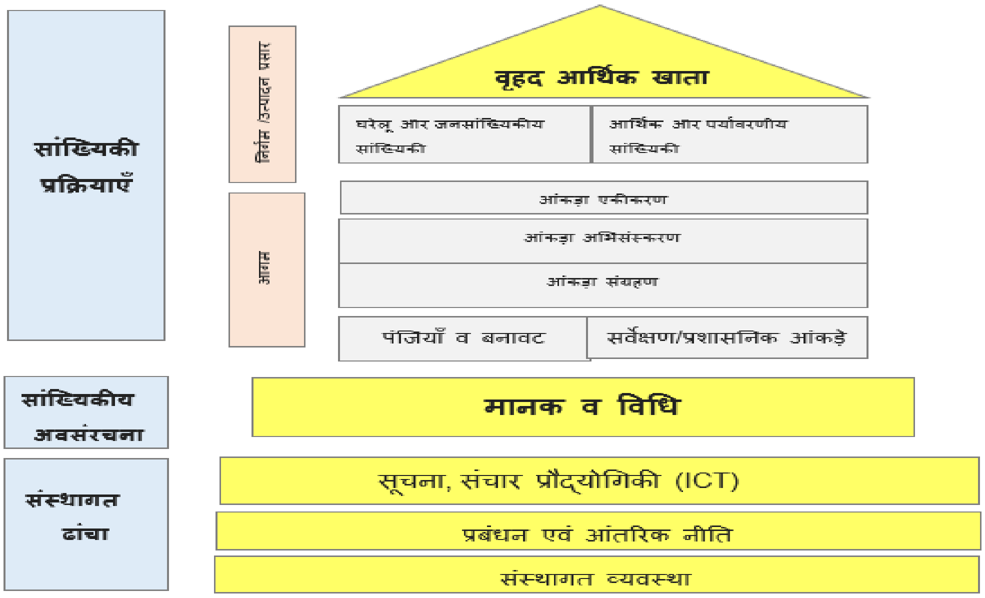

ज. पंचवर्षीय कार्यनीतिक लक्ष्य और गतिविधियाँ

ज.। विषय-वस्तु, लक्ष्य और कार्यनीतिक गतिविधियाँ

विषय-वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियाँ
1.संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण	1.1 एक प्रभावी कानूनी और नीति सांख्यिकीय ढांचा स्थापित करना	1.1.1 शासकीय सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति तैयार की जाएगी और राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार प्रक्रियाओं में तेजीलाने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयकी भूमिका और जिम्मेदारियों को अधिसूचित किया जाएगा।
		1.1.2 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का सुदृढ़ीकरणकरने पर एक बिल का मसौदा तैयार किया जाएगा तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली कोकार्यनीतिक दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करने और आँकड़े गुणवत्ता आश्वासन के लिए

विषय-वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियाँ
		राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोगको एक पेशेवर स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से संसद में पेश किया जाएगा।
		1.1.3 सांख्यिकीय उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन ढांचा तैयार / विकसित करना।.
		1.1.4 एजेंसियों में प्रशासनिक आंकड़ों के उपयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए एक ढांचा तैयार करना।.
		1.1.5 आँकड़ासमेकन की सुविधा के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना।
		1.1.6 जो आँकड़े सार्वजनिक अनुक्षेत्र में नहीं हैं उनका प्रयोगकरते समय पेशेवर नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की विभिन्न समितियों के सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करना।
		1.1.7 एसडीजी की निगरानी के लिए ढांचे को सुदृढ़करना।
		1.1.8 डेटा प्रसार संरचना और उपयोगकर्ता जुड़ाव को निम्नलिखित के माध्यम सेसुदृढ़करना क. प्रमुख सांख्यिकीय उत्पादों के लिए अग्रिम दर्शिका जारी करने ख. प्रसार और उपयोगकर्ता जुड़ाव के लिए मीडिया नीति / सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयकी योजना का विकास ग. नियमित आंकड़ा निर्माता-उपयोगकर्ता सम्मेलन और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया तंत्र
	1.2 सांख्यिकीय प्रक्रमोंव प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरणकरना, और नए सांख्यिकीय उत्पादों को विकसित करना	1.2.1 सुधार के लिए गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के संबंध मेंमौजूदा सांख्यिकीय उत्पादों / प्रक्रियाओं का आकलन करना
		1.2.2 केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों, उनके मेटाआंकड़ों और विधायी प्रावधानों के आँकड़े समुच्चय और रजिस्ट्रियों का एक संग्रह तैयार करना।
		1.2.3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहित केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय आंकड़ोंऔर मेटाडेटा विनिमय क्रमाचार विकसित करना

विषय-वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियाँ
		1.2.4 अर्थव्यवस्था की नियमित निगरानी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का तथ्य पत्रक का प्रकाशन करना।
		1.2.5 राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवसाय पंजी का विकास करना
2. सांख्यिकीय प्रणाली के प्रौद्योगिकीय और भौतिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	2.1 शासकीय सांख्यिकी के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच विकसित करना	2.1.1 शासकीय सांख्यिकी के लिए राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पोर्टल / डेटा भंडार विकसित करना।
		2.1.2 सभी सामाजिक-आर्थिक घरानों और स्थापना सर्वेक्षणों के लिए आईटी आधारित सामान्यीकृत सर्वेक्षण समाधान (जी एस एस) का विकास और कार्यान्वयन
	2.2 अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी का सुदृढ़ीकरण	2.2.1 बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए मौजूदा तंत्र कानवीकरण।
	2.3 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयका भौतिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	2.3.1 संवर्धित दक्षता के साथ सांख्यिकीय गतिविधियों के प्रभावी समन्वय के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयके लिए भवनखरीद।
3. प्रभावी मानव पूंजी प्रबंधन	3.1 कौशल का संवर्धन	3.1.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता का आकलन करना और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों में प्रणाली व्यापक राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति विकसित करना।
		3.1.2 सरकारी सांख्यिकी में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संगठनों की पेशेवर सांख्यिकीय सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक सलाहकारी संस्था सह नवाचार सेल की स्थापना।
		3.1.3 प्रशिक्षण के लिए नीतिगत ढांचा
	3.2 शासकीय सांख्यिकी पर प्रशिक्षण-अवसंरचना को बढ़ाना	3.2.1 एन एस एस टी एके भौतिक और आईटी अवसंरचना को मजबूत करना।
		3.2.2 अखिल भारतीय स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए आंचलिक / क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।

ज.।। विजन- 2024 के लिए आक्रमणशील समयसीमा

10.1 पूर्ववर्ती अनुच्छेद में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एग्रेसिव घटनाक्रम और निरंतर निगरानी के साथ मील के पत्थर स्थापित करते हुए गतिविधियों कातीव्रता से पता लगाने की आवश्यकता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयके विजन 2024 को भौतिक, वित्तीय और प्रौद्योगिकीय तौर-तरीकों के रूप में हितधारक मंत्रालयों / विभागों से अपेक्षित सहयोग के साथ मंत्रालय के भीतर तालमेल और समन्वित विज़न की आवश्यकता वाली चरण / घटक-वार गतिविधियों के माध्यम से साधाजाएगा। विभिन्न कार्यनीतिक समुच्चयों की समयसीमा निम्नलिखित विवरण में दी गई है ।

ज.III विभिन्न कार्यनीतिक गतिविधियों का विवरण और समयसीमा

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण	1.1 उचित कानूनी और नीति ढांचा स्थापित करना	1.1.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में सुधार प्रक्रियाओं के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयको सक्षम करने के लिए शासकीयसांख्यिकी (एन पी ओ एस) पर राष्ट्रीय नीति तैयार और अधिसूचित की जाएगी	1. एनपीओएस पर मंत्रिमंडल टिप्पणी को अंतिम रूप देना और अंतर-मंत्रिमंडल परामर्श के लिए परिचालित करना।	एनपीओएस के क्रियान्वयन पर वर्षात प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयन पर अनुवर्तीकार्यवाही करना	एनपीओएस के क्रियान्वयन पर वर्षात प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयन पर अनुवर्तीकार्यवाही करना	एनपीओएस के क्रियान्वयन पर वर्षात प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयन पर अनुवर्तीकार्यवाही करना	एनपीओएस के क्रियान्वयन पर वर्षात प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्यवाही करना
			2. मंत्रिमंडलकी मंजूरी लेना				
			3. कार्यान्वयन के लिए कार्य-योजना को अंतिम रूप देना।				
			एनपीओएस के				

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			कार्यान्वयन हेतुखाका तैयार करने के लिए एक कार्य-दल का गठन				
			एक एनपीओएस कार्यान्वयन सेल की स्थापना।				
		1.1.2 एन एस सीको एक पेशेवर स्वायत्त संस्था जो राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली को कार्यनीतिक दिशा, मार्गदर्शन और गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करेगी, के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से	संसद में पेश किए जाने वाले एनएससी विधेयक के मसौदे के विभिन्न रूपों को अंतिम रूप देंना	संसद द्वारा एनएससी विधेयक को मंजूरी देने के बाद, एनएससी अधिनियम और नियमों को लागू करने के लिए प्रक्रिया	केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों में सांख्यिकीय प्रणालियों और कामकाज की समीक्षा में एनएससी की सुविधा के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों में सांख्यिकीय प्रणालियों और कामकाज की समीक्षा में एनएससी की सुविधा के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	एनएससी और एनएससी अधिनियम के काम के कार्यान्वयन की समीक्षा
			एनएससी विधेयक का	अधिनियम के प्रावधानों के			

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एन एस सी) पर मसौदा विधेयक संसद में पेश किया जाएगा	मसौदा तैयार करना और मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना	कार्यान्वयन के लिए एनएससी सचिवालय को सुदृढ़ किया जाना			
			संसद में एन एस सीविधेयक पेश करना				
		1.1.3 सांख्यिकीय उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन ढांचे (क्यू ए एफ) को अनुकूलित / विकसित करना	आंकड़ागुणवत्ता आश्वासन प्रभाग (डी क्यू ए डी) स्थापित करना	भारत के लिए एक क्यू ए एफको अपनाने पर कार्य-दल का प्रतिवेदन, और एक मूल्यांकन उपकरण समूह	प्रतिवेदन और प्रशासनिक आंकड़ोंदोनों में गुणवत्ता आश्वासन लागू करना।	सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता के तीसरेस्कंध के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना	सार्वजनिक अनुक्षेत्र में उत्पाद विशिष्ट गुणवत्ता तथ्य प्रतिष्ठापन
			एम.एस.पी.आई. के मुख्यदल को डेटा गुणवत्ता आश्वासन	सांख्यिकीय कर्मियों के लिए क्यू ए एफपरएक			

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			विधियोंसंबंधी पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ पर एक्सपोजर/ प्रशिक्षण	प्रशिक्षण मॉड्यूलका विकास करना।			
			शीर्ष 5 चयनित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांख्यिकीय उत्पादों केआधारभूत मूल्यांकन के लिएमूलभूतदल की देखरेख में सर्वेक्षण पद्धति में क्यूएअवधारणाएं लागू करना				
			भारत के लिए शासकीय सांख्यिकी हेतु एक क्यू ए एफको				

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			विकसित / अनुकूलित करने के लिए एक कार्य-दलका गठन				
		1.1.4 एजेंसियों में प्रशासनिक सांख्यिकी के उपयोग को संवर्द्धित रूप से बढ़ाने के लिए एक ढांचा तैयार करना	एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति (आई एम सी) की स्थापना				
			मंत्रालयों के बीच निर्णयों / परिणामों को साझा किया जाए,और कम से कम त्रैमासिक आयोजित की जानेवाली, आई एम सीकी नियमित बैठकों की एक प्रणाली प्रस्तुत करना।				
		1.1.5 डेटा		मंत्रालयों के पास डेटा की			

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		समेकन सुविधा के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना		उपलब्धता पर और अन्य मंत्रालयों की आवश्यकताओं के आधार पर,अनुमोदन के लिए आईपी के माध्यम सेडेटा साझा करने की सुविधा के लिए मसौदा संलेखतैयार किए जाने है।			
				एन आई आई पीके माध्यम से डेटा साझा करने के लिए संलेख हेतु आई एम सीकी स्वीकृति			
		1.1.6	पेशेवर नैतिकता				

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		जो आँकड़े सार्वजनिक अनुक्षेत्र में नहीं हैं उन्हें प्रयोग करते समय पेशेवर नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए एमओएसपीआई की विभिन्न समितियों के सदस्यों पर आचार संहिता लागू करना।	की संहिता तैयार करना और इसे कार्यान्वयन के लिए सूचित करना				
		1.1.7 एसडीजी की निगरानी के लिए ढांचे को सुदृढ़ करना।	एनआईएफ, आदि की समीक्षा के लिए केंद्र स्तर पर एसडीजी व्यवस्था पर उच्च स्तरीय समिति की नियमित बैठकें।	राज्य स्तरीय एसडीजी की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे (एसआईएफ) का विकास	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बातचीत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी निगरानी क्षमता को मजबूत करना	राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर एसडीजी की अद्यतन स्थिति पर रिपोर्ट जारी करना	राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर एसडीजी की अद्यतन स्थिति पर रिपोर्ट जारी करना
			एसडीजी और	एसआईएफ	एसडीजी पर राज्य		विश्व की तुलना में

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			एनआईएफ पर अंतर्राष्ट्रीय विकास पर कार्यशालाओं/ सम्मेलनों का आयोजन करने जैसे राज्य सरकारों के क्षमता निर्माण उपाय शुरू करना	की समीक्षा सहित एसडीजी के मुद्दों पर राज्यों में उच्च स्तरीय समितियों का गठन	सरकारों की क्षमताओं में वृद्धि।		देश में एसडीजी प्रगति की राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा
				राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर एसडीजी पर अद्यतन स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करना	राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर एसडीजी पर अद्यतन स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करना		
				एसडीजी पर डेटा अंतराल को दूर करने के लिए राष्ट्रव्यापी			

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				सर्वेक्षण शुरू करना			
		1.1.8 डेटा प्रसार संरचना और उपयोगकर्ता जुड़ाव को मजबूत करना		'औपचारिक निर्गमनदिनद र्शिका' के आधार परकेंद्रीय मंत्रालयों के सांख्यिकीय उत्पादों के समेकित निर्गमनदिनद र्शिका को संकलित और प्रसारित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	सभी सांख्यिकीय उत्पादों के लिए अग्रिम निर्गमन दिनदर्शिका' को औपचारिक रूप देने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ काम करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।	सभी सांख्यिकीय उत्पादों के लिए अग्रिम निर्गमन दिनदर्शिका' को औपचारिक रूप देने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ काम करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।	सभी सांख्यिकीय उत्पादों के लिए अग्रिम निर्गमन दिनदर्शिका' को औपचारिक रूप देने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ काम करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
				विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी	विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी आंकड़ों	विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी आंकड़ों	विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी आंकड़ों

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				आंकड़ों की उपलब्धता और आवश्यकता की समीक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रक-विशिष्ट डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलनों के आयोजन को व्यवस्थित या सुविधाजनक बनाने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	की उपलब्धता और आवश्यकता की समीक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रक-विशिष्ट डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलनों के आयोजन को व्यवस्थित या सुविधाजनक बनाने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	की उपलब्धता और आवश्यकता की समीक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रक-विशिष्ट डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलनों के आयोजन को व्यवस्थित या सुविधाजनक बनाने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	की उपलब्धता और आवश्यकता की समीक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रक-विशिष्ट डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलनों के आयोजन को व्यवस्थित या सुविधाजनक बनाने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
				मीडिया योजना तैयार करना और जन		ऑनलाइन प्रतिक्रिया तंत्र को लागू करना	

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				जागरूकता अभियान शुरू करना			
					नियमित आधार पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयके त्रैमासिक समाचार पत्र प्रकाशित करना।	प्रमुख विश्वविद्यालयों और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में भारत सांख्यिकी कार्यक्रम का आयोजन करना	
	1.2 सांख्यिकीय प्रक्रियाओं और प्रक्रमों को सुदृढ़ करना, और नए सांख्यिकीय उत्पादों का विकास करना	1.2.1 सुधार के लिए गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के संबंध मेंमौजूदा सांख्यिकीय उत्पादों / प्रक्रियाओं का आकलनकरना		डी क्यू ए डीऔर एफ ओ डीसे शुरू करके, क्यू ए एफपर सांख्यिकीय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।	अनुशंसित क्यू ए एफ के अनुसार कुछ , 30, सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता का आकलन	गुणवत्ता के स्तरों की उपलब्धि पर रिपोर्ट	तृतीयस्कंध डेटा गुणवत्ता मूल्यांकन

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					मूल्यांकन सांख्यिकीय उत्पादों और इन्हें प्राप्त करने के लिए समयसीमा हेतु प्राप्त की जाने वाली गुणवत्ता के स्तर को निर्धारित करना	क्यू ए एफप्रोत्साहन के लिए योजना लागू करना	क्यू ए एफप्रोत्साहन के लिए योजना लागू करना
					क्यू ए एफको आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों को प्रोत्साहित करने और उत्साहवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित करना		शोधन के लिए क्यू ए एफकी समीक्षा
		1.2.2 केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के	मेटाआंकड़ों के साथ प्रमुख सांख्यिकीय संकेतकों के लिए	अन्य सांख्यिकीय संकेतकों और उनके	राज्य सरकारों के सांख्यिकीयआँकड़े समुच्चय को शामिल करने के	मेटाडेटा सामंजस्य के लिए फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर तैयार	एसडीएमएक्स, एपीआई, आदि का उपयोग करके मेटाडेटा फ्रेमवर्क

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		सांख्यिकीय आँकड़े समुच्चय और रजिस्ट्रियों, उनके मेटाआंकड़ोंऔर विधायी प्रावधानों का एक संग्रह तैयार करना	केंद्रीय मंत्रालयों के सांख्यिकीय डेटा समुच्चय और रजिस्ट्रियों के संग्रह की तैयारी	मेटाआंकड़ोंके लिए केंद्रीय मंत्रालयों के सांख्यिकीय आँकड़े समुच्चय और रजिस्ट्रियों के संग्रह की तैयारी करना	लिए संग्रह का विस्तार करना। मेटाडेटा मैपिंग और सॉफ्ट सुसंगत मैपिंग के लिए काम शुरू करना	करना और हितधारकों के परामर्श से अंतिम रूप देना	आर्किटेक्चर के गतिशील अद्यतनीकरण के लिए प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देना।
		1.2.3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित केंद्र व राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा विनिमय प्रोटोकॉल विकसित करना	एसडीएमएक्स पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	शासकीय आँकड़ों के संकलन के आधार पर केंद्रीय मंत्रालयों की सांख्यिकीय डेटा आवश्यकताओं को समेटना और समेकित करना	सरकारी उद्देश्यों के लिए सांख्यिकीय डेटा एकत्र करने के लिए एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय समाशोधन सदन तैयार करना		
			सांख्यिकीय	केंद्रीय			

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			कर्मियों के लिए एसडीएमएक्स पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	मंत्रालयों के एसडीएमएक्स परसांख्यिकीय कर्मियों का प्रशिक्षण			
				आंकड़ोंऔर मेटाडेटा विनिमय प्रोटोकॉल के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापनों आदि के माध्यम से व्यवस्थाओं को औपचारिक रूप देना			
				इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के			

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				साथ समझौता ज्ञापन			
		1.2.4 भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतर निगरानी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के तथ्य पत्रक प्रकाशित करना।	मासिक आधार पर भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आकलन करने के लिए 100 + सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की सूची तैयार करना	मासिक आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के 25 प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की एक गतिशील तथ्य पत्रक प्रकाशित करना।	मासिक आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के 50प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की एक गतिशील तथ्य पत्रक प्रकाशित करना।	मासिक आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के 75 प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की एक गतिशील तथ्य पत्रक प्रकाशित करना।	मासिक आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 + प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की एक गतिशील तथ्य पत्रक प्रकाशित करना।
		1.2.5 राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यापार रजिस्टर (एनएसबीआर)तैयार करना	7वीं आर्थिक जनगणना (ईसी) का संचालन करना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना, एनएसबीआर के विकास के लिए	राज्यों / संघ शासित प्रदेशों की रजिस्ट्रियों / आंकड़ों के आधार पर एक गतिशील बिजनेस रजिस्ट्रर तैयार करना	8वीं आर्थिक जनगणना (ईसी) का संचालन करना	

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				कार्यान्वयन की कार्यनीति निर्धारित करना			
			7 वीं ईसी के परिणाम जारीकरना	एनएसबीआर के विकास के लिए 5 राज्यों में कार्यान्वयन	एनएसबीआर के विकास के लिए 25राज्यों में कार्यान्वयन	एनएसबीआर के विकास के लिए सभीराज्यों में कार्यान्वयन	
			केंद्र/राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के रजिस्टरों का संकलन और अध्ययन				
			एनएसबीआर के विकास पर एक अवधारणा पत्र तैयार करना				
2 सांख्यिकीय प्रणाली के प्रौद्योगिकीय और भौतिक अवसंरचना को	2.1 सरकारी आंकड़ों के लिए एक एकीकृत	2.1.1 शासकीय आंकड़ों के लिए डेटा वेयरहाउस सहित राष्ट्रीय एकीकृत	एन आई आई पीके विकास के लिए एक एजेंसी को काम पर रखने के लिए आर एफ	एन आई आई पीमें 5 प्रमुख मंत्रालयों से सांख्यिकीय डेटा के	एन आई आई पीमें 15 प्रमुख मंत्रालयों से सांख्यिकीय आंकड़ोंके समेकन के लिए चरणबद्ध	एन आई आई पीऔर प्रमुख राज्य सरकारों में 15 प्रमुख मंत्रालयों से सांख्यिकीय	केंद्र और राज्य सरकार एजेंसियों के सभी प्रमुख शासकीय आँकड़े समुच्चयों के

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मजबूत करना	प्रौद्योगिकी मंच विकसित करना	सूचना पोर्टल (एनआईआईपी) विकसित करना	पी का प्रारंभ; सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन और ऑनबोर्डिंग	समेकन के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन	कार्यान्वयन	आंकड़ोंके समेकन के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन	भंडारऔरएन आई आई पी के एक-स्टॉप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनने सहित,एन आई आई पीमें सभी सांख्यिकीय डेटाबेस और रजिस्ट्रियों का समेकन
			एनआईआईपी, जीएसएस और एमओएसपीआई की अन्य आईटी पहलों के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक पीएमयू की स्थापना	एनआईआईपी में राज्य सरकार डी ई एस के आंकड़ोंका चरणबद्ध समेकन	एनआईआईपी में राज्य सरकार डी ई एस के आंकड़ोंका चरणबद्ध समेकन	एनआईआईपी में राज्य सरकार डी ई एस के आंकड़ोंका चरणबद्ध समेकन	
			सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन				

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			मंत्रालयआंकड़ोंको एन आई आई पीमें एकीकृत किया जाना है।				
		2.1.2 सभी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए आईटी आधारित सामान्यीकृत सर्वेक्षण समाधान (जी एस एस) का विकास और कार्यान्वयन	जीएसएस के विकास के लिए एक एजेंसी को काम पर रखने के लिए आरएफपी का प्रारंभ	सर्वेक्षण प्रबंधन के लिए पैरा-आंकड़ोंके उपयोग पर पर्यवेक्षी और डेटा गुणवत्ता प्रबंधन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	चरणबद्धविज़न में एनएसएस सर्वेक्षण(राज्य के नमूने) के लिए राज्य सरकारों हेतुजीएसएस का उपयोग बढ़ाया जाना	चरणबद्धविज़न में एनएसएस सर्वेक्षण(राज्य के नमूने) के लिए राज्य सरकारों हेतु जीएसएस का उपयोग बढ़ाया जाना	
			जीएसएस के विकास के लिए एजेंसी का चयन	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयके सभी प्रकार केसर्वेक्षणों के लिए जी एस	राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के लिए लाइन मंत्रालयों द्वारा उपयोग के लिए जीएसएस का उपयोग बढ़ाया जाना		

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				एसका उपयोगकरना			
			सर्वेक्षण प्रबंधन के लिए पैरा-आंकड़ोंके उपयोग पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयकी मुख्य टीम का प्रशिक्षण / एक्सपोजर	चरणबद्धविज़न में एनएसएस सर्वेक्षण (राज्य के नमूने) के लिए राज्य सरकारों हेतु जीएसएस का उपयोग बढ़ाया जाना	जीएसएस का उपयोग राज्य सरकारों तक पहुंचाया जाएगा।		
	2.2 अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी को सुदृढ़ करना	2.2.1 बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए मौजूदा तंत्र में सुधार करना।	केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (ओसीएमएस) के सुधार हेतुएक एजेंसी को काम पर रखने के लिए	विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए संशोधित उपयोगकर्ता के अनुकूल ओसीएमएस	डेटा गुणवत्ता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुधार किए गए ओसीएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों का प्रशिक्षण।		

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			आरएफपी को अंतिम रूप देना	का विकास करना और शुरू करना			
			ओसीएमएसके सुधार के लिए एजेंसी को काम पर रखने के लिए आरएफपी का प्रारंभ	सुधार किए गए ओसीएमएस के उपयोग के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों का प्रशिक्षण			
			ओसीएमएस में सुधार करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन				
	2.3 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	2.3.1 संवर्धित दक्षता के साथ	एनबीसीसीसे भवन की खरीद के लिए पीआईबी मेमो के ड्राफ्ट को			सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का	

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	मंत्रालयके भौतिक अवसंरचना को मजबूत करना	सांख्यिकीय गतिविधियों के प्रभावी समन्वय के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयके दिल्ली कार्यालयों के लिए भवन की खरीद	ऑनलाइन अपलोड करना			खुद का एकीकृत भवन।	
			भवन की खरीद के प्रस्ताव पर पीआईबी द्वारा मूल्यांकन				
			प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी				
			बजट का प्रावधान				
			कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भवन की खरीद के लिए एनबीसीसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर	परियोजना कार्यान्वयन जारी है	परियोजना कार्यान्वयन जारी है	कार्यालय परिसर की साज-सज्जा।	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयकार्यालयों को नए भवन में शिफ्ट करना।
			सूचना और राष्ट्रीय सांख्यिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु खरीद के लिए	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना,	भवन परिसर के निर्माण के लिए पीआईबी नोट का मसौदा तैयार करना और आवश्यक	भवन निर्माण की शुरुआत (3-4 साल लगने की संभावना)	

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			भूमि की पहचान करना	कार्यान्वयन की कार्यनीति बनाना	अनुमोदन प्राप्त करना.		
3. प्रभावी मानव पूंजी प्रबंधन	3.1 कौशल का संवर्धन	3.1.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता का आकलन करना और सरकारी आंकड़ों में प्रणाली व्यापक राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति विकसित करना	राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के कौशल की आवश्यकता के आकलन के लिए एक एजेंसी को शामिल करना।	कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करनाऔर सांख्यिकीकर्मियों तैनाती से जोड़ना			
			एनएसएसटीए एजेंसी की सिफारिशों की जांच करना और समयबद्ध्‍ कार्यान्वयन के लिए ढांचा तैयार करना	कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना			
			कार्यनीतिक				

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं (चिन्हित एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन, प्रशिक्षण कैलेंडर, ट्विनिंग कार्यक्रम आदि)				
			सांख्यिकीय सर्वेक्षण प्रगणकों, पर्यवेक्षकों और डेटा गुणवत्ता प्रबंधन के लिए पाठ्यक्रमों तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास	पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से कर्मियों की तैनाती के लिए सर्वेक्षण प्रगणकों, पर्यवेक्षकों और डेटा गुणवत्ता के लिए			

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			निगम (एनएसडीसी) के साथ सहयोगकरना।	सांख्यिकीय पाठ्यक्रम मॉड्यूल लागू करना। .			
		3.1.2 सरकारी संगठनों की पेशेवर सांख्यिकीय सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने और सरकारी सांख्यिकीमें अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सांख्यिकीय परामर्श सह	उद्योग, शिक्षा और नागरिक समाज के साथ सहयोगात्मकविज़न का उपयोग करते हुए सांख्यिकीय परामर्श-सह-नवाचार सेल की स्थापना करना	सर्वेक्षण आंकड़ोंऔर प्रशासनिक आंकड़ों में डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए लाइव परियोजनाएं का संचालन करना। राष्ट्रीय सांख्यिकी में सुधार के लिए प्रयोगशाला से क्षेत्र अनुसंधान	केंद्रीय और राज्य स्तरों पर अधिक लाइव परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों में परामर्श और अनुसंधान एवं विकास कौशल से लैस प्रशिक्षित पेशेवर	केंद्रीय और राज्य स्तरों पर अधिक लाइव परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सांख्यिकीयआंकड़ों में परामर्श और अनुसंधान एवं विकास कौशल से लैस प्रशिक्षित पेशेवर	अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और परामर्श राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली का अभिन्न अंग होना

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		नवाचार सेल की स्थापना करना		को प्रोत्साहित करना			
		3.1.3 प्रशिक्षण के लिए नीतिगत ढांचा	सरकारी आंकड़ों और कार्यान्वयन कार्यनीति पर प्रशिक्षण नीति तैयार करना	केंद्र और राज्य सरकारों, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा वितरण और उपयोग के लिए नियमित कार्यशालाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/ इंटरनेट वीडियो सीडी/डीवीडी का उत्पादन,के माध्यम से प्रसारण/वेब	उभरते क्षेत्रों यथा बिग डाटा, पाठ विश्लेषण,कृत्रिम बौद्धिकता, डीप लर्निंग, यांत्रिक अध्ययन, इंटरनेटसंबंधी वस्तु पैटर्न मान्यता, भविष्यवाची अध्ययन आदि में डिजाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।		एनएसएसटीए को सरकारी आंकड़ों में प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				कास्ट जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से, डिजाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनसंख्या के विभिन्न क्षेत्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम।			
			सी ए पी आईसमाधान का उपयोग करने के लिए क्षेत्र जांचकर्ताओं हेतु शासकीय आंकड़ों पर ई-अध्ययनडिजाइन	अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं और राज्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक आंकड़ों हेतु अनिवार्य	उपयोगकर्ताओं के लिए आंकड़ोंको अधिक सार्थक बनाने के लिएडेटा पत्रकारिता और विज़ुअलाइज़ेशन में कौशल विकास के लिए कार्यक्रम तैयार		

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1 31.3.2020 तक	वर्ष 2 1.4.2020-31.3.2021	वर्ष 3 1.4.2021-31.3.2022	वर्ष 4 1.4.2022-31.3.2023	वर्ष 5 1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिजाइन	करना।		
			मुख्यई- अध्ययन मॉड्यूल का संचालन करना औरइसकी प्रतिक्रिया परिष्कृत करना				
			ई- अध्ययनका प्रचारकरने के लिए अभियान शुरू करना।				
	3.2 शासकीय आंकड़ों पर प्रशिक्षण अवसंरचना में वृद्धि करना	3.2.1 एन एस एस टी एके भौतिक और आईटी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	सूचना और राष्ट्रीय सांख्यिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए खरीद हेतु भूमि की पहचान	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), कार्यान्वयन की कार्यनीति तैयार करना।	भवन निर्माण की शुरुआत (3-4 साल लगने की संभावना)	भवन परिसर का निर्माण जारी है (2024-25 में पूरा होने की संभावना)	भवन परिसर का निर्माण जारी है (2024-25 में पूरा होने की संभावना)
			एन एस एस टी				

कार्यनीतिक फोकस / विषय वस्तु	लक्ष्य	कार्यनीतिक गतिविधियां	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
			31.3.2020 तक	1.4.2020-31.3.2021	1.4.2021-31.3.2022	1.4.2022-31.3.2023	1.4.2023-31.3.2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			एके लिए अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के लिए डीआईबी ज्ञापन तैयार करना				
		3.2.2 अखिल भारतीय स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रीय / प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना	शासकीय सांख्यिकीमेंक्षेत्रीय / प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए एफ ओ डीके क्षेत्रों / प्रदेशों की सुविधाओं का उन्नयन				

*****